



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017 / ज्येष्ठ 2, 1939

No. 139]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/JYAISTHA 2, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

अंतिम जांच परिणाम

*विषय:* चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सीविंग मशीन नीडल्स" के आयातों के संबंध में निर्णयिक समीक्षा जांच।

**फा. सं. 15/02/2016-डीजीएडी।—1.** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को मेसर्ज एल्टेक बेसल लिमिटेड (जिसे आगे याचिकादाता अथवा आवेदक भी कहा गया है) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सीविंग मशीन नीडल्स" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटन-रोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

**2.** यतः प्राधिकारी ने दिनांक 19 मई, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14/10/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरूआत की थी और प्राधिकारी ने 6 मई, 2011 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे जिसमें उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22 जून, 2011 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 50-2011-सीमा-शुल्क के द्वारा निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए थे।

**3.** यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा निर्णयिक समीक्षा जांच शुरू करने को यथोचित सिद्ध करने के लिए प्रदत्त पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार दिनांक 10 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 15/02/2016-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की

समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की वैधता को केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या 37/2016-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा 21 जून, 2017 तक बढ़ा दिया गया था।

4. वर्तमान समीक्षा जांच के कार्य-क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उपरोक्त वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

**क. क्रियाविधि**

5. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के संबंध में निम्नोक्त वर्णित क्रियाविधि का अनुसरण किया गया है:
  - i. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने चीन जनवादी गणराज्य से "सीविंग मशीन नीडल्स" का निरंतर पाटन होने का आरोप लगाया गया है।
  - ii. प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन प्राप्त करने के बारे में भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को सूचित किया था।
  - iii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 10 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी।
  - iv. प्राधिकारी ने भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास और चीन जनवादी गणराज्य से ज्ञात निर्यातिकों, आयातकों, उपभोक्ताओं को और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जांच की शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजी थीं और उनसे अनुरोध किया था कि वे जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 40 दिन के भीतर अपने लिखित विचारों से अवगत करा दें।
  - v. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू करने के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया गया था और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातिकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध किया गया था। निर्यातिकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति निर्यातिकों के नाम एवं पतों सहित उन्हें भी भेजी गई थीं।
    1. हेमेन सिटी मेतु नीडलमेकिंग कंपनी लिमिटेड
    2. जियांगसु मेस सीविंग मशीन नीडल्स कंपनी लिमिटेड
    3. हेमेन डाली सीविंग मशीन नीडल्स कंपनी लिमिटेड
    4. स्वोर्ड मशीन नीडल कंपनी लिमिटेड
    5. फ्लाइंग टाइगर नीडल कंपनी लिमिटेड
    6. नान फैंग नीडल कंपनी लिमिटेड
  - vi. बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) की प्रश्नावलियां चीन जनवादी गणराज्य में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातिकों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबद्ध सूचना प्रदान कर दें।
  - vii. तथापि, उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में किसी भी निर्यातिक ने निर्यातिक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
  - viii. प्राधिकारी ने आवश्यक सूचना मंगवाने के लिए जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति आयातक की प्रश्नावली के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नावली प्रेषित की गई थी (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) और उन्हें सलाह दी गई थी कि वे नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने लिखित विचारों से अवगत करा दें।
    1. मदुरा कोट्स प्राईवेट लिमिटेड
    2. अश्विन इंटरकॉन्टेनेट
    3. ग्रोज बैकर्ट एशिया प्राईवेट लिमिटेड

4. कोहिनूर इम्पेक्स
5. सनी इंटरनेशनल
6. पॉल ब्रोज कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
7. स्लीक कार्पोरेशन
8. नीडल इंडिया (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
- ix. तथापि, संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन एम्बरोएट्री कार्ड क्रिएटर नामक एक आयातक ने क्लिटिंग मशीन नीडल्स पर शुल्क लगाने के विरोध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।
- x. संबद्ध देश में चाईना चेम्बर ऑफ कार्मस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स नामक निर्यातकों की एक एसोसिएशन ने केवल निवेदन किए हैं, लेकिन उसने विस्तृत प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। वर्तमान निर्धारण में उनके द्वारा किए गए निवेदनों पर भी विचार किया गया है।
- xi. प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए उसे खुला रखा है।
- xii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए अनुबंध-3 में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की यथासंभव जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटनरोधी शुल्क, पाटन मार्जिन से कम होता है तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiii. वर्तमान जांच में जांच की अवधि जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2015 तक की है। तथापि, क्षति की अवधि में वर्ष 2012-213, 2013-14, 2014-15 और जांच की अवधि को भी शामिल किया गया है।
- xiv. जितना आवश्यक समझा गया है, आवेदक और हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मंगाई गई थी। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का जितना आवश्यक समझा गया है, सत्यापन किया गया है।
- xv. सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित भारत में संबद्ध वस्तु की अनुकूल उत्पादन-लागत, और विनिर्माण एवं विक्री लागत की गणना की गई जिससे यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो क्या वह घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रहेगा।
- xvi. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से आयात के कारोबार-वार आंकड़े मंगाए गए थे और उन्हें भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस अधिसूचना में अपनाया गया है। महानिदेशक, प्रणाली से भी आंकड़े मंगाए गए हैं। याचिकादाता ने क्षति का विश्लेषण करने के लिए चीन के सीमा-शुल्क विभाग से प्राप्त हुए नियांत्रित आंकड़ों पर विश्वास किया है। इसी स्रोत का उपयोग याचिका दायर करते समय भी किया गया था। प्राधिकारी ने चीन के सीमा-शुल्क विभाग से प्राप्त हुए आंकड़ों पर विश्वास किया है जिन्हें याचिकादाता द्वारा याचिका दायर करते समय प्रदान किया गया था। तथापि, इस अंतिम जांच परिणाम में विश्लेषण करने के लिए जांच की कार्रवाई के दौरान डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त हुए विस्तृत कारोबार-वार आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।
- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें तथा ऐसे अगोपनीय वृत्तान्त को प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अनुसार बना कर रखी गई सार्वजनिक फाईल में रखा गया है।
- xviii. प्राधिकारी ने नियम 6 (6) के प्रावधान के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए 20 फरवरी, 2017 को मौखिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई के समय जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे, उन्हें सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप

- में भी प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट किए गए विचारों के प्रत्युत्तर देने का अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए निवेदनों पर उचित रूप से विचार किया है।
- xix. मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान जिन निर्यातकों, उत्पादकों और हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच के संबद्ध सूचना प्रदान नहीं की है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है।
- xx. दिनांक 30.03.2017 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचारार्थ अनिवार्य तथ्य निहित थे। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि प्रकटन विवरण पर उन्हें यदि कोई टिप्पणी करनी है, तो ऐसी टिप्पणियां 06.04.2017 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुई टिप्पणियों पर उचित रूप से विचार किया है।
- xxi. इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा \*\*\* सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय माना गया है।
- xxii. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमेरिकी डॉलर = 64.60 रुपए है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
6. विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सीविंग मशीन नीडल्स" हैं।
- घरेलू उद्योग के निवेदन**
7. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- वर्तमान जांच के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद में गृहों और औद्योगिक दोनों प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली "सीविंग मशीन नीडल्स" शामिल हैं। सीविंग मशीन नीडल्स के दोनों वर्गों में से प्रत्येक के अंतर्गत अनेक आकार और प्वाइंट स्टाइल (सामान्य, बॉल प्वाइंट, लेदर प्वाइंट आदि) आते हैं। नीडल्स के अनेक प्रकार होते हैं जिनका इस्तेमाल बोवन, निट परिधान सिलने, चर्म, कढ़ाई आदि के लिए किया जाता है। विभिन्न नीडल्स को "सिस्टम" के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सिस्टम में अनेक आकारों की नीडल्स होती हैं। प्रत्येक आकार के लिए विभिन्न प्वाइंट स्टाइल्स हो सकते हैं।
  - सीविंग मशीन नीडल का विनिर्माण करना एक सघन प्रोद्योगिकी का कार्य है। नीडल के विनिर्माण में 12 प्रमुख कार्यों के साथ 100 से भी अधिक अन्य कार्य निहित होते हैं। सीविंग मशीन नीडल बहुत सूक्ष्मता से सुनिश्चित किए जाने वाला माइक्रोन परिशुद्धता का साधन है। तथापि, मशीन कितनी भी आधुनिक हो, नीडल सिले गए उत्पाद की सीविंग उत्पादकता के निष्पादन और सौंदर्य परक परिष्करण का निर्धारण करती है।
  - नीडलों का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित मशीनें विशेष प्रयोजन की मशीनें होती हैं जिनका डिजायन स्वतः विनिर्माताओं द्वारा बनाया जाता है और ये किन्हीं अन्य स्थानों पर उपलब्ध नहीं होती हैं। हाउसहोल्ड नीडल्स का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनरी का उपयोग मूल प्रणालियों की औद्योगिक सीविंग मशीन का विनिर्माण करने के लिए भी किया जा सकता है। विगत वर्षों में परिवारों की नीडल्स की मांग घट रही है और व्यवसायिक दर्जियों की पारिवारिक मशीनों के बजाए औद्योगिक मशीनों का उपयोग करने के प्रति प्रवृत्ति बढ़ने के कारण औद्योगिक नीडल्स का उपयोग बढ़ रहा है। औद्योगिक नीडल्स की मूल प्रणाली की कीमतें वहीं हैं, जो कि परिवारों की नीडल्स की हैं।
  - सीविंग मशीन नीडल को सीविंग मशीन में फिट किया जाता है और उसका उपयोग अनेक प्रकार के उत्पाद को सीने के लिए किया जाता है। नीडल्स का अनुप्रयोग अनेक किस्मों के लिए किया जाता है, जिनमें से प्रमुख इस्तेमाल बोवन, निट परिधान सिलने, कशीदाकारी और चर्म आदि के लिए किया जाता है। इनके अतिरिक्त फर्निशिंग, डॉल मेकिंग, जिल्डसाजी, व्हेकल सीट कवर आदि जैसे अन्य कार्य में भी इनका प्रयोग किया जाता है। सीविंग मशीन नीडल सामान्यतया अंकों में उत्पादित की जाती है और बेची जाती है। तथापि, महत्वपूर्ण सूचना भार (किलोग्राम) से प्रदर्शित होती है। भार को संख्या में परिवर्तित करने का औद्योगिक मानदंड 1 किलोग्राम = 1,667 नीडल्स होता है। सीविंग मशीन नीडल्स को सामान्यतया छोटे बॉक्स में पैक किया जाता है। ऐसे प्रत्येक बॉक्स में दस नीडल्स निहित होती हैं। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मानकीकृत पैकिंग होती है।
  - संबद्ध वस्तुएं सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 84 के अंतर्गत आती हैं और इनका आयात अनेक उप-शीर्षों के अतिरिक्त एचएस संहिता के अंतर्गत उप-शीर्ष 8452.30 के अंतर्गत किया जाता है।

- vi. घरेलू और आयातित उत्पाद में नियोजित प्रोद्योगिकी और गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। याचिकादाता विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहा है और उसे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में (विकसित और विकासशील बाजारों में) अनेक उपभोक्ताओं को बेच रहा है।
- vii. याचिकादाता ने यह बताया है कि वह अपनी विनिर्माण क्रियाकलाप की शुरूआत से ही अनेक प्रकार की सीरिंग मशीन नीडल्स का विनिर्माण कर रहा है। विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर याचिकादाता ने यह बताया है कि वह क्लिंटिंग मशीन नीडल्स भी विनिर्मित कर रहा है और वह इनका विनिर्माण, मूल जांच के दौरान भी कर रहा था। याचिकादाता अपना यह दावा सभी प्रकार की सीरिंग मशीन नीडल्स के लिए उत्पाद केटेलॉग के साथ किया है, जिसमें क्लिंटिंग मशीन नीडल्स भी शामिल हैं।

### अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

8. एम्बरोएडरी कार्ड क्रिएटर ने बताया है कि "क्लिटिंग मशीन नीडल" को विचाराधीन उत्पाद के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सीरिंग मशीन नीडल्स का अभिप्राय उन्हीं नीडल्स से होना चाहिए जिनका उपयोग सीने के लिए किया जाता है और जिन्हें भारत में विनिर्मित किया जा रहा है तथा इनके आयात से घरेलू उद्योग को धूति हो सकती है। एम्बरोएडरी कार्ड क्रिएटर ने आगे यह भी बताया है कि भारत में "क्लिटिंग मशीन नीडल" का कोई विनिर्माता नहीं है और इस मद के आयातों की मात्रा बहुत सीमित है। उनका यह प्रतिवेदन है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से "क्लिटिंग मशीन नीडल" को बाहर रखा जाना चाहिए और साथ ही विगत शुल्क अधिसूचना के लिए भी उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सीरिंग मशीन नीडल्स" है। विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर गृहों और औद्योगिक दोनों प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली "सीरिंग मशीन नीडल्स" शामिल हैं। सीरिंग मशीन नीडल्स के दोनों वर्गों में से प्रत्येक के अंतर्गत अनेक आकार और प्वाइंट स्टाइल (सामान्य, बॉल प्वाइंट, लेदर प्वाइंट आदि) आते हैं। सीरिंग मशीन नीडल्स को सीरिंग मशीन में फिट किया जाता है और उसका उपयोग अनेक उत्पादों की सिलाई करने के लिए किया जाता है। नीडल्स का उपयोग व्यापक किस्मों के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इन प्रमुख उत्पादों में परिधानों की सिलाई, कशीदाकारी और चमड़े के उत्पाद शामिल हैं। इनके अतिरिक्त इसके अनेक अन्य अनुप्रयोग भी हैं, जैसे कि फर्नीशिंग, गुडिया बनाना, किताबें सिलना, वाहनों की सीट के कवर को सिलना आदि।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एम्बरोएडरी कार्ड क्रिएटर नामक आयातक ने प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के अर्थ और कार्य-क्षेत्र का प्रतिवाद इस आधार पर किया है कि क्लिटिंग मशीन नीडल्स नामक मद को न तो सीरिंग मशीन नीडल्स में और न ही घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद में शामिल किया गया है। तथापि, मामले के तथ्यों की जांच करने पर भिन्न तथ्य का पता चला है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे को नोट किया है कि वह क्लिटिंग मशीन नीडल्स विनिर्मित कर रहा है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि क्लिटिंग मशीन नीडल्स को संबद्ध वस्तुओं के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखने के एम्बरोएडरी कार्ड क्रिएटर के दावे का कोई महत्व नहीं है।

11. विचाराधीन उत्पाद वही बना हुआ है जो कि मूल जांच में था। इस उत्पाद को सीमा-शुल्क अधिनियम के अध्याय 84 में एचएस संहिता 8452-30 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्रा है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र पर वाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

12. समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु से है, जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक द्विष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक द्विष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हों।"

13. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि आवेदक के उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और दोनों वस्तुएं, भौतिक गुण-क्षमताओं, प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में तुलनीय हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है और दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

14. प्राधिकारी रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से आगे यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में तुलनीय हैं। आगे यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने विगत जांच में भी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जांच की थी, जिस पर आवश्यक संशोधन सहित वर्तमान समीक्षा जांच में भी विश्वास किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं, नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं तथा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित परिभाषा और कार्य-क्षेत्र के भीतर ये समान वस्तुएं हैं।

15. इस प्रकार प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार के समान वस्तु है।

#### ग. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र और स्थिति

##### घरेलू उद्योग के निवेदन

16. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- याचिका मेसर्ज एल्टेक बेसल लिमिटेड, केलाम्बक्कम द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता, मेसर्ज एल्टेक बेसल लि. केलाम्बक्कम के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य उत्पादक हैं। मेसर्ज टी वी एस सीविंग नीडल्स लिमिटेड ने कथित रूप से निरंतर पाटन के परिणामस्वरूप अपना प्रचालन बंद कर दिया है। अन्य दो उत्पादक, मेसर्ज श्मेत्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्ज ग्रॉज बेक्ट एशिया प्राईवेट लिमिटेड पात्र नहीं हैं क्योंकि वे यूरोपीय यूनियन में विद्यमान जर्मनी कंपनी की सहायक कंपनियां हैं, जो कि जर्मन में अपनी मूल कंपनियों से संबंधित विभिन्न नीडल्स का आयात, भारत में पुनः विक्री करने के लिए कर रही हैं और साथ ही जर्मनी में अपनी मूल कंपनी को अपने समग्र उत्पादन का नियंता भी कर रही हैं।
- अतः मेसर्ज एल्टेक बेसल लिमिटेड ही भारत में संबद्ध वस्तुओं की एकमात्र पात्र घरेलू उत्पादक है और नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उत्पादक बनती है।
- याचिकादाता ने संबद्ध वस्तुओं के आयात नहीं किए हैं। याचिकादाता संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी नियंता क अथवा आयातक से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इस प्रकार याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और 5 (3) के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग है।

##### अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

17. किसी भी आयातक, उपभोक्त, नियंतक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है।

##### प्राधिकारी द्वारा जांच

18. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ब) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के नियंतकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शब्द का तात्पर्य केवल शेष उत्पादकों से होगा। ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।"

19. यह आवेदन-पत्र मेसर्ज एल्टेक बेसल लि. केलाम्बक्कम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक अन्य ज्ञात उत्पादक मेसर्ज टी वी एस सीविंग नीडल्स लिमिटेड ने अपना प्रचालन बंद कर दिया है। मेसर्ज श्मेत्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड तथा मेसर्ज ग्रॉज बेक्ट एशिया प्राईवेट लिमिटेड जर्मनी में स्थित अपनी मूल कंपनी की 100% सहायक कंपनियां हैं। वे अपने संपूर्ण उत्पादन का नियंता अपनी मूल कंपनी को करती हैं तथा भारत में पुनः विक्री के लिए जर्मनी स्थित अपनी संबंधित मूल कंपनियों से विभिन्न प्रकार की नीडल्स का आयात करती हैं। तदनुसार प्राधिकारी का यह मानना है कि याचिकादाता पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार घरेलू उद्योग के आधार को पूरा करता है और नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है।

### **घ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**

#### घरेलू उद्योग के निवेदन

20. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चाईना चेम्बर ऑफ कामर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स ("सीसीसीएमई") द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है। न ही किसी निर्यातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत किया है।
- ii. प्राधिकारी कृपया इन हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसी सूचना (निर्यातक की प्रश्नावली के रूप में, सीसीसीएमई के ब्यौरे और सीसीसीएमई के सदस्यों की सूची) प्रस्तुत करें अथवा कम से कम सूचना का अगोपनीय वृतान्त प्रस्तुत करें ताकि घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो सके।
- iii. पाटन-रोधी विधि और नियमावली के अनुसार निर्यातकों को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उसका अगोपनीय वृतान्त अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करना चाहिए। तथापि, वर्तमान जांच में निर्यातकों द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग निर्यातकों की एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ स्वयं के बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ नहीं है।
- iv. घरेलू उद्योग ने ऐसी किसी भी सूचना के गोपनीय होने का दावा नहीं किया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। वास्तव में यदि कोई सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है, तो कोई भी इन हितबद्ध पक्षकारों को उसे अधिप्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। वास्तव में सीसीसीएमई ने ऐसा दावा किया है कि उसने कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") की बेवसाईट से याचिकादाता के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सूचना एकत्रित की है। सीसीसीएमई भी कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") की बेवसाईट से ऐसी सूचना का अधिगमन करने का दावा कर सकता है।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रपत्र-IV A में विशिवत आंकड़े दिए गए हैं और यह प्रपत्र स्थापित पद्धति के अनुसार है।

#### अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

21. प्रतिवादी निर्यातकों की एसोसिएशन, चाईना चेम्बर ऑफ कामर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स ("सीसीसीएमई") द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. नियम 7 का प्रयोजन, पाटन-रोधी जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को पर्याप्त रूप से समझने के लिए समर्थ बनाना है। याचिका के अगोपनीय वृतान्त से पक्षकारों को समग्र जांच में सुरक्षा के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- ii. वर्तमान याचिका का अगोपनीय वृतान्त नियम 7 में निर्धारित मानक को पूरा करने में विफल रहा है।
- iii. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उसने अपूर्ण याचिका दायर की है।
- iv. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को निर्देश देना चाहिए कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचीबद्ध आंकड़ों के साथ एक अद्यतन प्रपत्र-IV A तत्काल प्रस्तुत करे।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृतान्त को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध करा दिया है।

23. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।"

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

24. विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार में गोपनीय सूचना के बारे में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"अनुच्छेद - 6.5: ऐसी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरणार्थ क्योंकि उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा अथवा उसके प्रकटन से उक्त सूचना प्रदाता किसी व्यक्ति पर अथवा जिस व्यक्ति से उक्त सूचना प्राप्त की गई है, उस व्यक्ति पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा जिसे किसी जांच हेतु पक्षकारों ने गोपनीय आधार पर प्रदान किया है, उस सूचना को बेहतर कारण दर्शाएं जाने पर प्राधिकारियों द्वारा गोपनीय ही माना जाएगा। ऐसी सूचना का प्रकटन सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - 6.5.1: प्राधिकारी गोपनीय सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेंगे। ये सारांश यथोचित विस्तार में होंगे ताकि गोपनीय रूप में प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके।

अनुच्छेद-6.5.2 : आपवादित परिस्थितियों में ऐसे पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार नहीं किया जा सकता। ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में ऐसे कारणों का विवरण दिया जाना चाहिए कि इसका सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

अनुच्छेद-6.5.2: यदि प्राधिकारी यह पाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसके प्रकटन का प्राधिकार प्रदान करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं बशर्ते उचित स्रोतों से उनकी संतुष्टि होने के उपरांत यह प्रदर्शित हो सके कि उक्त सूचना सही है।

अनुच्छेद-6.5.2 की पाद टिप्पणी (विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी करार की पाद टिप्पणी 18) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि गोपनीयता के अनुरोधों को स्वैच्छकि ढंग से अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।"

25. इस प्रकार यह सुस्पष्ट होता है कि प्राधिकारियों द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से गोपनीयता के प्रावधानों के अध्यधीन होती हैं और इनसे किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचनी की गोपनीयता सुरक्षित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त गोपीनीय सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष भी गोपनीय बनता है, जब किसी भी तरह से ऐसे निष्कर्ष के प्रकटन के फलस्वरूप गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई गोपनीय सूचना का प्रकटन होता है।

26. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत अंतिम जांच परिणाम से पहले अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन का उपबंध निर्धारित किया गया है। नियम 16 के अंतर्गत भी जबकि अगोपनीय तथ्यों का प्रकटन, सभी हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष किए जाने की आवश्यकता है, गोपनीय तथ्यों का प्रकटन, "संबंधित हितबद्ध पक्षकारों" के समक्ष किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी चरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतिस्पर्धी और परस्पर-विरोधी हितों के पक्षकारों को गोपनीय सूचना का प्रकटन करने का अधिकार नहीं है।

27. जांच को सुकर बनाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को विश्वास और भरोसे से प्रस्तुत की गई वाणिज्यिक रूप से संवेदी और गोपनीय सूचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों थेट्रों में बाजार के वातावरण को पूर्णतया संदूषित कर देगी। घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, क्षति रहित कीमत आदि से संबंधित गोपनीय सूचना का प्रकटन, घरेलू के साथ-साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धीयों को अनुचित लाभ प्रदान करेगा और उपभोक्ताओं के समक्ष उन्हें अलाभप्रद स्थिति में रख देगा।

28. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच, पाटन-रोधी नियमावली और विश्व व्यापार संगठन के करार में निहित उपबंधों के अनुसार गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट हो जाने पर, जहां कही भी आवश्यक हुआ है, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है।

29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्द्धी और पारस्पर विरोधी हितों के हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष गोपनीय सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता है। तथापि, सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त का प्रकटन, हितबद्ध पक्षकारों को कर दिया गया है।

### **झ: विविध निवेदन**

#### **घरेलू उद्योग के निवेदन**

30. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के बाद भी घरेलू उद्योग को निरंतर नुकसान हो रहा है, जिसके बहुविध कारण हैं - (क) चीन के निर्यातकों द्वारा पाटन-रोधी शुल्क की प्रवंचना, (ख) भारतीय आयातकों द्वारा मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क का अपवंचन और (ग) पहले लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क की अपर्याप्त मात्रा, जिसके फलस्वरूप आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम बनी हुई है।
- ii. आयात के आंकड़ों से मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, विएतनाम, स्विटजरलैंड और यू.के. से अत्यधिक कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के काफी मात्रा में आयात होने का पता चलता है। याचिकादाता के स्वतंत्र अनुसंधान के अनुसार इन देशों में विनिर्माण सुविधाएं उस सीमा तक विद्यमान नहीं हैं, जिससे ऐसा समझा जाए कि इन देशों में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के आयात नहीं हो रहे हैं और वास्तव में इन वस्तुओं का उत्पादन चीन में हो रहा है और उनका निर्यात इन देशों के माध्यम से किया जाता है।
- iii. कोरिया, जर्मनी, जापान और चैक गणराज्य जैसे अन्य देशों, जिनकी अपनी निजी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित हैं, से आयातों से ऐसा देखा जा सकता है कि ऐसे आयात वास्तविक रूप से चीन की कीमतों से अधिक कीमतों पर किए जा रहे हैं।
- iv. याचिकादाता ने चीन से आयातों की मात्रा और मूल्य के लिए चीन के सीमा-शुल्क के आंकड़ों को अपनाया है क्योंकि डीजीसीआईएंडएस और चीन के सीमा-शुल्क से अधिप्राप्त किए गए आंकड़ों के बीच काफी अंतर विद्यमान है, जिससे ऐसा पता चलता है कि डीजीसीआईएंडएस ने समग्र आंकडे अधिप्राप्त नहीं किए हैं।
- v. विगत में ऐसे अनेक मामले हुए हैं, जिनमें डीजीएडी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित सूचना को नहीं अपनाया है और उसके बजाए अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को अपनाया गया है, जिनमें निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर, निर्यातक देश अथवा भारत में द्वितीयक स्रोत के सीमा-शुल्क के आंकडे शामिल हैं।
- vi. तथापि, चीन के निर्यात आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस के आयात के आंकड़ों के बीच व्याप्त अंतर के बारे में सीसीसीएमई द्वारा बहुत उचित रूप से उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन सीसीसीएमई ने भारत को निर्यातों के बारे में चीन में सूचित किए गए 9310 लाख अदद के लुप्त होने के मुद्दे की अनदेखी की है।
- vii. इसके अतिरिक्त कम आंकड़ों से यह भी पता चलेगा कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में पर्याप्त स्तर पर गिरावट आई है, लेकिन जिसके बारे में सार्वजनिक अथवा अन्यथा कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, जिससे ऐसा पता चले कि मांग में घोर गिरावट आई है। इस प्रकार डीजीसीआईएंडएस द्वारा सूचित आंकड़ों की अशुद्धता का पता चलता है।
- viii. पाटन-रोधी शुल्क लगाने से आयात रुकेंगे नहीं, लेकिन इससे केवल आरोपित पाटित आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग को व्यापार करने का समानान्तर कार्य-क्षेत्र उपलब्ध होगा।
- ix. सीसीसीएमई का यह दावा सही नहीं है कि चीन में नीडल्स के प्रमुख उत्पादकों को दिवालिया हो गया है क्योंकि चीन से नीडल्स के आयातों में ऐसी कोई नाटकीय गिरावट नहीं आई है, जिससे उसके विनिर्माण यूनिटों के बंद होने का पता चलता हो।
- x. अन्य देशों से निर्यात के विपरीत  $0.42$  प्रति नीडल की औसत कीमत पर चीन से वस्तुओं के निर्यात हुए हैं, जो कि  $2.45$  रूपए -  $8.08$  प्रति अदद की सीमा में उसकी कीमत है। इसलिए चीन से निर्यात निश्चित रूप से भारत में पाटित किए जा रहे हैं।
- xi. चीन के उद्यमियों और याचिकादाता के बीच कीमत का उत्तरदायितव लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

#### **प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन**

31. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया था कि लगभग 3469 लाख अदद की तुलना में चीन से आयात केवल 72 लाख अदद हैं। इसका अभिप्राय यह है कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात, कुल आयातों का केवल 2% हैं। आयातों में ऐसी गिरावट, 2151% तक के अधिक पाटन-रोधी शुल्क के कारण आई है, जो संभव नहीं है।
- ii. (2) यदि घरेलू उद्योग अपनी 100% क्षमता प्रचालित करता है, तब भी वह कुल मांग के 23% से अधिक की पूर्ति नहीं कर पाएगा। जहां तक कि चीन के उत्पादों पर अन्तसुने 2125% तक के अधिक पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बाद भी याचिकादाता अपनी क्षमता का सबसे अधिक 53% का ही उपयोग कर सका है।
- iii. चीन की ऐसी कुछ बड़ी निर्यातिक कंपनियों में जिनका उल्लेख मूल पाटन-रोधी जांच में किया गया था, हेमेन मेर्इटू नीडल्स कंपनी, हेमेन लिडा नीडल्स कंपनी, स्वार्ड नीडल्स कंपनी और सउदर्न नीडल्स कंपनी शामिल हैं, जिनका पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बाद दिवालिया हो गया है। इस समय चीन में सीरिंग नीडल उद्योग के दस से भी कम उद्यमी हैं, जो सभी क्षमता के घटने की समस्या का सामना कर रहे हैं। चीन के केवल तीन उद्यमी वर्तमान निर्णाय समीक्षा जांच में भाग ले रहे हैं।
- iv. निर्णाय समीक्षा जांच में भाग लेने वाले चीन के तीन उद्यमी वास्तव में निर्यातिक की प्रश्नावली के उत्तर देने के पात्र नहीं हैं क्योंकि निर्णाय समीक्षा जांच की अवधि के दौरान उनके पास निर्यात का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार उनके पास इस जांच में पाटन के भाग के लिए अपनी रक्षा करने के सिवाएँ और कोई विकल्प नहीं है।
- v. चीन से उत्पाद भारत में निम्न-अंत बाजार और परिवार के प्रयोक्ताओं के निमित्त होते हैं। इस प्रकार याचिकादाता के प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी कोरिया जनवादी गणराज्य और ताईवान की कंपनियां हैं और न कि चीन के उत्पादक।
- vi. चीन के उद्यमी याचिका के साथ कीमत संबंधी उत्तरदायित्व लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे भारत में निर्यात की मात्रा और कीमत को सीमित बनाए रख सकें। इस समग्र प्रक्रिया से भारत के निचले स्तर तक के उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति होगी और याचिकादाता चीन के उत्पादों के आयात के बारे में अधिक चिंतित नहीं होगा।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

32. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि मांग और पूर्ति के बीच अंतर व्याप्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि घरेलू उद्योग का यह दायित्व नहीं है कि वह घरेलू बाजार में समग्र मांग को पूरा करे। चूंकि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने से आयात की रोकथाम नहीं होती है और इसका उद्देश्य पाटन के कारण उत्पन्न अनुचित स्थिति में सुधार करना मात्र है, इसलिए प्रयोक्ता क्षेत्र सदैव आयात कर सकता है और अपनी अतिरिक्त मांग को पूरा कर सकता है।
33. प्रवंचना से संबंधित तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पाटन-रोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा जांच है और न कि प्रवंचना-रोधी कार्रवाई। इसलिए इस पहलु की जांच करना, इस जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर है।
34. इस तर्क के संबंध में कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में चीन से समग्र आयात शामिल नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के सीमा-शुल्क विभाग के आयात के आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस के आयात के आंकड़ों में व्यापक अंतर विद्यमान है। यह अंतर चौंकाने वाला है, लेकिन फिर भी यह नहीं माना जा सकता है कि भारतीय बाजार को गंतव्य वस्तुओं को तृतीय देशों की ओर इसलिए परवर्तित कर दिया गया है क्योंकि कुल आयात के आंकड़ों से भी ऐसे आरोप का पता नहीं चलता है। उसके बाद प्राधिकारी ने अनुसंधान के कार्य-क्षेत्र को व्यापक बना दिया था और डीजीसीआईएंड से विभिन्न एचएस संहिताओं के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के किए गए आयात के आंकड़े मंगाए थे और इसके अतिरिक्त डीजी प्रणाली से भी आंकड़े अधिप्राप्त किए थे। क्षति विश्लेषण करने के लिए कारोबार-वार आधार पर संकलित डीजीसीआईएंड द्वारा प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त आयात आंकड़ों पर अब विचार किया जा रहा है।
35. संबद्ध देश में उत्पादकों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के साथ कीमत की जिम्मेदारी लेने की उनकी इच्छा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत संबंधी जिम्मेदारी केवल प्राधिकारी और निर्यातकों के बीच ही ली जा सकती है और वह भी जबकि संबद्ध देश से निर्यातिक प्राधिकारी को सहयोग दें। संबद्ध देश से किसी भी निर्यातिक ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है और इस प्रकार कीमत संबंधी जिम्मेदारी लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

#### **च. बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

#### घरेलू उद्योग के विचार

36. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके अतिरिक्त उसका कोई भी निर्यातिक, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत किए जाने के लिए न्यायालाल से विकसित प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

- ii. भारत चीन के लिए एक उचित प्रतिनिधि देश है क्योंकि इसके फलस्वरूप वह सही और पर्याप्त सूचना का अभिगमन कर सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य जांच प्राधिकारियों ने भी भारत को एक उचित प्रतिनिधि देश के रूप में माना है।
- iii. भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण, विधिवत् समायोजन करने पर इस तथ्य को ध्यान में रख कर किया गया है कि बिक्री कीमत, घाटे को पूरा करने वाली कीमत है।
- iv. याचिकादाता ने निर्यात कीमत का परिकलन करने के लिए चीन के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा प्रदत्त कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- v. विभिन्न किस्मों के उत्पादों की लागत और कीमत में व्याप्त विशेष अंतर को ध्यान में रखते हुए याचिकादाता ने प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए पृथक निर्यात कीमत निर्धारित की है।
- vi. यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका ने अनेक मामलों में भारत को एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के रूप में माना है। इसलिए यूरोपीय कमीशन के प्रेक्षणों और निर्धारणों को मात्र इस कारण से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि उनके द्वारा निर्धारित किया गया मार्जिन, भारत द्वारा निर्धारित किए गए मार्जिन से अधिक है। हालांकि चीन से यूरोप को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद की निर्यात कीमत, भारत को किए जाने वाले निर्यात की कीमत से बहुत अधिक है, फिर भी भारत में पाटन मार्जिन, यूरोप द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन की तुलना में कम है।
- vii. याचिकादाता ने निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को कच्चे माल की खपत, परिवर्तनीय लागत और कीमत निर्धारण के अन्य संबद्ध आंकड़ों की व्यापक सूचना प्रस्तुत की है।

#### हितबद्ध पक्षकारों के विचार

37. पाटन मार्जिन के संबंध में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है अथवा निवेदन नहीं किया है।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

38. जांच शुरू करने के चरण में प्राधिकारी ने इस अवधारणा पर कार्रवाई शुरू की थी कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश है। जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी थी कि वे जांच शुरू करने की सूचना का उत्तर दें और बाजार अर्थव्यवस्था के अपने दर्जे का निर्धारण करने से संबद्ध सूचना प्रदान करें। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए एमईटी की प्रश्नावली की प्रतियां, सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थीं। साथ ही प्राधिकारी ने चीन की सरकार से अनुरोध किया था कि वह चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध सूचना प्रदान करने की सलाह दें।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और चीन की सरकार को निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता के बारे में पर्याप्त रूप से अधिसूचित कर दिया गया था तथा उन्हें इस संबंध में अपने निवेदन करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन चीन से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी को वर्तमान जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है और न ही अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने नियमावली में यथा वर्णित कोई ऐसा अन्य वैकल्पिक आधार भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिस पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके।

40. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और चीन की किसी भी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकारी वर्तमान जांच में यह उपयुक्त समझते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाए और वे चीन जनवादी गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित अनुसार आगे की कार्रवाई की कार्रवाई करते हैं। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उपबंध है कि:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में विना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

41. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में घरेलू विक्री कीमत के आधार पर अथवा अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संरचित मूल्य अथवा ऐसे तृतीय देश से किसी अन्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है, निर्यात कीमतों के आधार पर करने की आवश्यकता है। तथापि, यदि उपरोक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण, किसी भी अन्य उचित आधार पर कर सकते हैं, जिसमें उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत और देय कीमत शामिल है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजन किया जाएगा।

42. इस प्रकार किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए किसी विश्वसनीय कीमत और लागत के ब्यौरे उपलब्ध नहीं होने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की संरचना, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत अथवा देय कीमत के आधार पर की है, जिसके लिए उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए उचित समायोजन किया गया है। तदनुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की अनुकूलतम लागत पर विचार करते हुए तथा व्याज रहित विक्रियों की लागत के 5% पर लाभ प्रदान करने के बाद चीन में सभी निर्यातिकों द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

#### चीन में सभी निर्यातिकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

43. चूंकि इस जांच में चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातिक ने भाग नहीं लिया है, इसलिए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। चीन जनवादी गणराज्य से सभी निर्यातिकों के संबंध में कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत का निर्धारण, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, एफओबी कीमत, पत्तन व्यय और भाड़े के व्यय के लिए उचित समायोजन करने के बाद किया गया है। इस प्रकार से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातिकों के संबंध में संरचित सामान्य मूल्य, निबल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

#### पाटन मार्जिन

44. उपरोक्त यथा प्रस्तावित संरचित सामान्य मूल्य और कारखाना-गत निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातिकों के लिए परिकलित किया गया पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

संरचित सामान्य मूल्य		निबल निर्यात कीमत		पाटन मार्जिन		पाटन मार्जिन	
रूपए/ लाख अदद	अमरीकी डालर/ लाख अदद	रूपए/ लाख अदद	अमरीकी डालर/ लाख अदद	रूपए/ लाख अदद	अमरीकी डालर/ लाख अदद	%	%
***	***	***	***	***	***	***	950-1000

#### छ. क्षति निर्धारण तथा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

##### घरेलू उद्योग के विचार

45. क्षति, क्षति की संभावना और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- चीन से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन हो रहा है।
- यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का गहन पाटन होने की संभावना है।
- विभिन्न आर्थिक प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है।
- विगत न्यूनतम तीन वर्षों में घरेलू उद्योग की विक्रियों में स्थित वृद्धि हुई है और अब यह ब्रेक-इवन स्तर पर पहुंच गई है। किसी भी समय विश्व भर में विभिन्न व्यापारियों के होने के कारण देश में न्यूनतम एक विलियन नीडल्स का भंडार बना रहता है जो कि आयातक कन्टेनर पूरी तरह से नीडल्स से भरे रहते हैं। चीन में एकल वितरक की प्रणाली विद्यमान नहीं है और वह सीधे और साथ ही व्यापारियों के माध्यम से विक्री करता है। इसलिए प्रत्येक व्यापारी किसी सुसंगत योजना के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को आवश्यक प्रभाव पड़ने में समय लगता है।

- v. याचिकादाता की नीडल्स की मांग बढ़ गई है और इसके फलस्वरूप याचिकादाता ने अपनी उत्पादन क्षमता को आधुनिक और उन्नत बनाने का निर्णय लिया है ताकि उत्पादकता, सुरक्षा और स्वचालित प्रचालनों में सुधार लाया जा सके और इसके फलस्वरूप याचिकादाता द्वारा अत्यधिक पूंजी निवेश करना पड़ा है। हाल ही में होने वाली लाभप्रदता से ऐसे निवेश के समग्र प्रभाव को देखा जा सकता है।

### अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

46. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- यदि घरेलू उद्योग 100% क्षमता को प्रचालित करता है, तो भी वह भारत में कुल मांग की केवल 15% की पूर्ति कर पाएगा। ऐसी स्थिति में भारत में आयात अनिवार्य और बाध्यकारी हैं। 2000% शुल्क लागू करने के बावजूद भी 94% मांग की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती है।
  - पाटन-रोधी शुल्क के रूप में 2000% संरक्षण प्राप्त करने के बाद भी घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता में और गिरावट आई है। मूल जांच की जांच अवधि में नकदी लाभ (10) था, जो कि वर्तमान निर्णायिक समीक्षा जांच की जांच अवधि में (175) हो गया है। यदि मौजूदा शुल्क का स्तर पर्याप्त नहीं है और उससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वर्तमान समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग को लगभग 100-600% के पाटन मार्जिन से भी निश्चित रूप से अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता नहीं मिलेगी।
  - एल्टेक के लागत के आंकडे (एल्टेक द्वारा एमसीए के साथ प्रस्तुत किए गए पीएंडएल लेखाओं) जैसा कि कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की बेवसाईट में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में किए गए लाभ के दावे के समनुरूप नहीं हैं।
  - याचिका में रोजगार पर पाटन के प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संस्थापित क्षमता के घटने के बावजूद घरेलू उद्योग ने कर्मचारियों की संख्या और वेतन को बढ़ाया है। घरेलू उद्योग के रोजगार और उत्पादकता प्रति दिवस में वृद्धि हुई है।
  - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की लागत की प्रवृत्ति (सीओपी) के बारे में किया गया दावा, उसके द्वारा कार्पोरेट मंत्रालय को प्रस्तुत की गई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में निहित सूचना से मेल नहीं खाता है और याचिका में किए गए दावे अनुकूल नहीं हैं।
  - घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण चीन से आयातों से भिन्न अन्य कारक हैं। याचिकादाता अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों का निदान करने में विफल रहा है, जिनका घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ा था।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

47. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू नियमों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण किया है।

- प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का निदान करता है।
- विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यप्रक्रिया जांच करने की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की वृद्धि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।
- घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (4) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

- "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और

संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

- iv. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार "इस धारा के अंतर्गत लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को जब तक समाप्त न कर दिया जाए, वह इस प्रकार से शुल्क लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा। परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।"
- v. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा 4 के अनुसार उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्रियों की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल विक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर विचार किया है।

#### मांग और बाजार का हिस्सा

48. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्रियों के सारांश के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार से डीजीसीआईएंड के आंकड़ों और साथ ही चीन के सीमा-शुल्क विभाग के आंकड़ों (जिन्हें याचिकादाता ने प्रदान किया है) के आधार पर निर्धारित की गई मांग निम्नानुसार है:-

#### (1) डीजीसीआईएंडएस के अनुसार

मांग	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
संबद्ध देश	लाख अदद	41	11	12	151
अन्य देश	लाख अदद	1,491	1,156	1,194	1,126
घरेलू उद्योग की विक्रियां	लाख अदद	274	327	355	366
कुल मांग	लाख अदद	1,805	1,495	1,560	1,642
<b>मांग में बाजार का हिस्सा</b>					
संबद्ध देश	%	2%	1%	1%	9%
अन्य देश	%	83%	77%	76%	69%
घरेलू उद्योग की विक्रियां	%	15%	22%	23%	22%
कुल मांग		100%	100%	100%	100%

49. क्षति अवधि और जांच अवधि में मांग में वृद्धि हुई है। मूल वर्ष मांग के मामूली से ऊचे स्तर को दर्शा रहा है। समग्र अवधि में अन्य देशों के हिस्से की तुलना में संबद्ध देश के हिस्से में वृद्धि हुई है। मूल वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की विक्री में वृद्धि हुई है और वह शेष क्षति अवधि में बाजार को बनाए रखने में समर्थ रहा है।

#### (2) चीन के सीमा-शुल्क विभाग के अनुसार

मांग	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
संबद्ध देश	लाख अदद	3,288	2,553	1,853	1,849
अन्य देश	लाख अदद	3,717	3,941	3,223	3,469
घरेलू उद्योग की विक्रियां	लाख अदद	274	327	355	366
कुल मांग	लाख अदद	7,279	6,821	5,431	5,683
<b>मांग में बाजार का हिस्सा</b>					
संबद्ध देश	%	45.17%	37.43%	34.12%	32.53%
अन्य देश	%	51.06%	57.77%	59.34%	61.04%
घरेलू उद्योग की विक्रियां	%	4%	5%	7%	6.43%
कुल मांग		100%	100%	100%	100%

50. याचिकादाता ने यह निवेदन किया है कि क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। मांग में संबद्ध देश के हिस्से में भी गिरावट आई है। तथापि, यह काफी बना हुआ है, जबकि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में 2.43% तक की मामूली वृद्धि हुई है और यह निम्न स्तर पर बना हुआ है।

#### ज. पाटित आयातों के मात्रा संबंधी प्रभाव

##### आयात की मात्रा और आयातों में बाजार का हिस्सा

51. आरोपित पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से अधिप्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है। याचिकादाता द्वारा दिए गए चीन के सीमा-शुल्क विभाग के आंकड़ों को भी नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

##### (1) डीजीसीआईएंड एस के अनुसार

आयातों की मात्रा	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
चीन	लाख अदद	41	11	12	151
अन्य देश	लाख अदद	1,491	1,156	1,194	1,126
कुल आयात	लाख अदद	1,531	1,168	1,205	1,276
<b>निम्नोक्त के संबंध में संबद्ध निर्यात</b>					
खपत	%	2%	1%	1%	9%
उत्पादन	%	10%	3%	2%	31%

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में गिरावट आई है। तथापि, ये आयात अभी भी काफी हैं। उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है और ये अभी भी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।

##### (2) चीन के सीमा-शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार

आयातों की मात्रा	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
चीन	लाख अदद	3,288	2,553	1,853	1,849
अन्य देश	लाख अदद	3,717	3,941	3,223	3,469
कुल आयात	लाख अदद	7,005	6,494	5,076	5,318
<b>निम्नोक्त के संबंध में संबद्ध निर्यात</b>					
खपत	%	45	37	34	33
उत्पादन	%	1417	555	387	386

53. याचिकादाता ने यह निवेदन किया है कि मूल वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में गिरावट आई है। तथापि, ये आयात अभी भी काफी हैं। उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में भी गिरावट आई है। तथापि, ये अभी भी काफी हैं। याचिकादाता ने यह भी निवेदन किया है कि यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो चीन से आयात बाजार को फिर से हथिया लेंगे।

#### झ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव

54. कीमत के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या आरोपित पाटित आयातों द्वारा कीमतों में अत्यधिक कटौती की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों का अत्यधिक सीमा तक हास करते अथवा कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकते, जो कि अन्यथा होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच, कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण होने, यदि कोई है, के संबंध में की गई है।

विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निबल विक्री वूसली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत की तुलना, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच लागत के साथ डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आंकड़ों के आधार पर की गई है।

### (i) कीमत में कटौती

55. आयातों की पहुंच कीमत की तुलना, जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की भारत में घरेलू विक्री कीमत के साथ करके कीमत में कटौती होने का मूल्यांकन किया गया है, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

आयातों की मात्रा	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/लाख अदद	***	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	प्रवृत्ति	100	367	200	50
निबल विक्री वसूली	रूपए/लाख अदद	***	***	***	***
निबल विक्री वसूली	प्रवृत्ति	100	99	102	103
कीमत में कटौती	रूपए/लाख अदद	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	सीमा %	70-80	20-30	50-60	80-90

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से काफी कम है, जिसके फलस्वरूप कीमत में काफी कटौती हो रही है।

### (ii) कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण

57. पाटित आयातों के कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण प्रभाव की जांच भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत, निबल विक्री वसूली और पहुंच मूल्य के संदर्भ में की गई है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

आयातों की मात्रा	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रूपए/लाख अदद	37,696	1,38,361	75,404	18,861
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	367	200	50
विक्रियों की लागत	रूपए/लाख अदद	***	***	****	***
		100	112	101	109
विक्री कीमत	रूपए/लाख अदद	***	***	****	***
सूचीबद्ध		100	99	102	103

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल वर्ष की तुलना में विक्रियों की लागत के साथ-साथ विक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, विक्री कीमत में वृद्धि विक्रियों की लागत में वृद्धि से कम है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत के साथ-साथ विक्रियों की लागत से कम है। इस प्रकार आयात घरेलू बाजार में कीमत ह्रास कर रहे हैं।

### (iii) कम कीमत पर विक्री

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर विक्री क्षति का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। क्षति रहित कीमत का आकलन किया गया है और उसकी तुलना संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के साथ की गई है, ताकि कम कीमत पर विक्री होने की सीमा का पता लगाया जा सके। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य, क्षति रहित कीमत से काफी कम है, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है।

क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
रूपए/लाख अदद	अमरीकी डालर/ लाख अदद	रूपए/ लाख अदद	अमरीकी डालर/ लाख अदद
***	***	***	900-950

60. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात की कीमत का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण उसे कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ रही है।

**ज. घरेलू उद्योग की आर्थिक प्राचल**

**(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा**

61. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों की मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

विवरण	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
क्षमता	लाख अदद	900	900	900	900
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	लाख अदद	395	419	479	479
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	121	121
क्षमता उपयोग	%	44%	47%	53%	53%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	121	121
घरेलू बिक्रियां	लाख अदद	274	327	355	366
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	130	133

62. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन की क्षमता स्थिर बनी रही है। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि हुई है। तथापि, देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद भी क्षमता उपयोग निम्न स्तर पर बना हुआ है।

**(ii) लाभ/हानि और निवेश पर प्रतिलाभ**

63. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	लाख अदद	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	101	109
बिक्री कीमत	लाख अदद	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	102	103
लाभ/(हानि)	लाख अदद	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(193)	(95)	(146)
लाभ/(हानि)	लाख अदद	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(231)	(123)	(195)
ब्याज पूर्व लाभ	लाख अदद	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(231)	(123)	(195)
नकद लाभ	लाख अदद	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(292)	(87)	(223)
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ - एनएफए	%	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	तीमा	(0-10)	(15-25)	(0-10)	(10-20)

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्रियों की लागत में वृद्धि, बिक्री कीमत में वृद्धि से बहुत अधिक है। यह नोट किया जाता है कि बिक्री कीमत, बिक्रियों की लागत से निम्नतर बनी रही है,

जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप समस्त क्षति अवधि में व्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ भी नकारात्मक बना रहा है। याचिकादाता ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से भारतीय बाजार में पाठित आयातों की निरंतर उपस्थिति, घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के समनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोक रही है।

**(iii) मालसूचियां**

65. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
औसत मालसूची	लाख अदद	17	19	28	32
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	168	189

66. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूचियों में वृद्धि हुई है।

**(iv) उत्पादकता**

67. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन के स्तर के समनुरूप प्रति दिन के साथ-साथ प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

विवरण	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	लाख नग	3	3	4	3
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	118	113
प्रति दिन उत्पादकता	लाख नग	1.08	1.15	1.31	1.31
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	121	121

**(v) रोजगार और वेतन**

68. रोजगार, वेतन और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

विवरण	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	103	108
वेतन	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	139	138
वेतन प्रति कर्मचारी	लाख रूपए प्रति कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	135	128

69. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में रोजगार और अदा किए गए वेतन में वृद्धि हुई है।

**(vi) पाटन की मात्रा**

70. संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन काफी है।

**(vii) संवृद्धि**

71. नीचे तालिका में दिए गए आंकड़ों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन और विक्रियों की मात्रा के रूप में सकारात्मक संवृद्धि दर्ज की है। तथापि, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे कीमत के प्राचलों के रूप में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन प्रतिकूल रहा है।

विवरण	मापन यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
उत्पादन	%	--	6%	14%	0%
घरेलू विक्रियों की मात्रा	%	--	19%	9%	3%
क्षमता उपयोग	%	--	3%	7%	0%
लाभ	%	--	***	(***)	***
नकद लाभ	%	--	***	(***)	***
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	--	(10-20)%	10-20	(0-5)

**(viii) पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता**

72. संबद्ध देश से पाठित आयातों की मौजूदगी से इस क्षेत्र में भारी निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ा है। नकारात्मक लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ के साथ-साथ बाजार के अथाह हिस्से से पता चलता है कि पाठित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की संबद्ध देश से क्षेत्र के लिए पूँजी निवेश जुटाने में घरेलू उद्योग के सामर्थ्य का गंभीर रूप से प्रभावित होने का पता चलता है।

**(ix) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

73. जांच से यह पता चलता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की अच्छी मांग है। संबद्ध देशों से पाठित आयातों की कीमतें घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुँच मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुँच मूल्य, घरेलू उद्योग की कीमतों में हास/न्यूनीकरण कर रहा है, जिसके कारण उसे वित्तीय धाटे हो रहे हैं। संबद्ध देशों से भिन्न अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है अथवा वे गैर-पाठित कीमतों पर नहीं हैं क्योंकि इन देशों द्वारा पेश की जा रही कीमतें बहुत अधिक हैं। उत्पाद की मांग से गहन प्रवृत्ति का पता चलता है और इसलिए यह घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी कारक नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संबद्ध देशों से पाठित वस्तुएं, घरेलू उद्योग के कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के लिए उत्तरदायी हैं।

**(xx) क्षति का समग्र मूल्यांकन**

74. घरेलू उद्योग की क्षति से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की जांच और विश्लेषण करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटन-रोधी शुल्कों की उपस्थिति के बावजूद पाठित कीमतों पर चीन से अत्यधिक आयात प्रवेश कर रहे हैं। ये पाठित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रहे हैं। आयातों की पहुँच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से भी काफी कम है। जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक और अत्यधिक हैं। संबद्ध देश से पाठित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और उसे कीमतों में वृद्धि करने के लिए रोक रहे हैं, जो कि पाटन नहीं होने के कारण हो जाती। उत्पादन और विक्रियों की मात्रा के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन नकारात्मक बना हुआ है और पाठित आयातों की उपस्थिति में कीमतों में वृद्धि करने की उसकी असमर्थता के कारण उसके निरंतर क्षति हो रही है। इस प्रकार प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग को निरंतर आर्थिक क्षति हुई है।

**ट. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध**

75. घरेलू उद्योग की आर्थिक क्षति, पाठित आयातों की मात्रा और कीमत में कटौती होने और कीमत के न्यूनीकरण होने के रूप में घरेलू उद्योग की कीमत पर पाठित आयातों के प्रभाव की उपस्थिति की जांच तथा पाटन-रोधी भारतीय नियमावली और करार में सूचीबद्ध अन्य सूचक प्राचलों की जांच प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाठित आयातों से भिन्न कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग की क्षति के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

**(i) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और उनकी कीमतें:**

76. याचिकादाता ने यह निवेदन किया है कि संबद्ध देश पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन के मूल की संबद्ध वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा कथित रूप से अन्य देशों के माध्यम से भेजी जा रही है ताकि शुल्कों की प्रवर्चना की जा सके। तथापि, प्राधिकारी नोट

करते हैं कि यह पाटन-रोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा जांच है और प्रवंचना रोधी कार्रवाई नहीं है। इस मुद्रे की विस्तार से जांच करना इस जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर है। यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से आयात अधिक कीमतों पर हैं अथवा मात्रा के रूप में नगण्य हैं।

**(ii) मांग में संकुचन:**

77. जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग अनुकूलतम स्तर पर अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। इस प्रकार मांग में संकुचन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए संभावित कारण नहीं है।

**(iii) खपत के पेटर्न में परिवर्तन:**

78. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पेटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

**(iv) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार की प्रतिबंधित पद्धतियां और प्रतिस्पद्धा:**

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार को प्रतिबंधित करने की ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**(v) प्रोद्योगिकी में विकास:**

80. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्रोद्योगिकी में विकास क्षति का कारक नहीं है।

**(vi) निर्यात निष्पादन:**

81. याचिकादाता ने विचाराधीन उत्पाद के निर्यात किए हैं। तथापि, निर्यात की लाभप्रदता को पृथक किया गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को हुई क्षति का दावा केवल घरेलू प्रचालनों के कारण किया गया है। इसलिए निर्यातों को घरेलू उद्योग की क्षति के दावे के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

**(vii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन:**

82. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकादाता एकल उत्पादक कंपनी है। घरेलू उद्योग की क्षति का दावा केवल विचाराधीन उत्पाद के कारण किया गया है।

**ठ. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृति होने की संभावना**

83. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के तर्क की जांच, क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना की जांच करने के लिए की है। निम्नोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने और घरेलू उद्योग की क्षति होने की संभावना है।

**(i) वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर**

84. यह नोट किया जाता है कि मूल और वर्तमान दोनों जांच में पाटन मार्जिन का स्तर अत्यधिक है। देश में अत्यधिक मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात, निरंतर पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। कीमत में कटौती होने, कम कीमत पर बिक्री होने, कीमत में ह्रास और कीमत के न्यूनीकरण होने के स्तर तथा चीन में क्षमता और भारत में मांग को ध्यान में रखते हुए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

**(ii) जांच पश्चात अवधि में आयातों की मात्रा**

85. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी जांच अवधि के बाद भी चीन से आयात उसी स्तर पर बने रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप आयातों में गहन वृद्धि होगी।

**(iii) भारतीय बाजार में कीमत आकर्षण**

86. चीन जनवादी गणराज्य से भारत को जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए जा रहे हैं, वह पाटन के निरंतर जारी रहने की संभावना की सूचक है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। इसलिए यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भारतीय कीमतें, चीन के उत्पादकों के लिए बहुत आकर्षक होंगी। इसलिए शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर ऐसी संभावना है कि संबद्ध देश के निर्यातक, अपनी अत्यधिक क्षमता को ध्यान में रख कर भारतीय बाजार में अपने उत्पादन को और अधिक सरणीबद्ध करने लगेंगे।

**(iv) चीन में विशाल उत्पादन क्षमता**

87. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास विशाल क्षमताएं विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग ने चीन में विभिन्न विनिर्माताओं के पास निम्नलिखित उत्पादन क्षमताएं विद्यमान होने के साक्ष्य प्रदान किए हैं। इसने आगे यह भी बताया है कि वर्तमान शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति के फलस्वरूप इस अतिरेक क्षमताओं का अपवर्तन भारत को कर दिया जाएगा जिससे घरेलू उद्योग की क्षति और गहन होगी।

क्रमांक	कंपनी का नाम	क्षमता (लाख अदद)
1.	जिआंग्सू फ्लाईंग टाईगर नीडल्स कंपनी लिमिटेड.	7000
2.	नांगटोंग झौंगडे मेर्किंग नीडल कंपनी लिमिटेड.	4000
3.	नांगटोंग व्हाईट क्रेन नीडल्स कंपनी लिमिटेड.	200

**(v) चीन के उत्पादकों का निर्यातोन्मुखीकरण**

88. याचिकादाता ने चीन के सीमा-शुल्क के अनुसार चीन से तृतीय देशों के निर्यातों का विश्लेषण किया है। यह देखा गया है कि क्षति अवधि में पाठित कीमतों पर चीन द्वारा 83,425 लाख अदद नीडल्स के निर्यात तृतीय देशों को किए गए हैं, जो कि भारत में कुल मांग से अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत में उत्पादन, बिक्रियों और खपत के संबंध में चीन द्वारा पाठित आयात काफी हैं। इनसे स्पष्ट पता चलता है कि चीन के उत्पादक निर्यातों पर गहन ध्यान संकेन्द्रित कर रहे हैं। शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इन निर्यातों को द्वारा पाठित कीमतों पर भारत को अपने निर्यातों को अपवर्तित कर दिए जाने की संभावना है।

**(vi) उत्पाद और भारतीय बाजार के कीमत संवेदी होने के रूप में घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता**

89. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता अपनी अधिप्राप्ति करने का निर्णय, मुख्यतया कीमत को ध्यान में रख कर करते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में संबद्ध देश से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता होने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तथ्य की संपुष्टि, संबद्ध देश द्वारा दीर्घावधिक पाटन पद्धति से होती है। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए और ऊपर उल्लिखित वर्तमान पाटन और पाटन और क्षति प्राचलों की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने और घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने की संभावना है।

**ड. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन**

90. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि में क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार से आकलित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
रुपए/लाख अदद	अमरीकी डालर/लाख अदद	रुपए/लाख अदद	अमरीकी डालर/लाख अदद
***	***	***	***

**ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**

91. प्रकटन पश्चात अनुरोध केवल घरेलू उद्योग से प्राप्त हुए हैं। उसमें उठाए गए मुद्दे पहले ही जांच के दौरान पूर्व में उठाए गए हैं और उन्हें उपयुक्त रूप से हल कर लिया गया है। तथापि, स्पष्टता के लिए हितबद्ध पक्षकारों की बातों की निम्नलिखित रूप में जांच की जा रही है :

- आयात की मात्रा और मूल्य के संबंध में, घरेलू उद्योग का कहना है कि प्राधिकारी द्वारा मानी गई आयात की मात्रा चीन के सीमाशुल्क के आंकड़ों में दी गई मात्रा से कहीं कम है, इसलिए उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे सीधे ही चीन के सीमाशुल्क आंकड़ों का सत्यापन करें।
- घरेलू उद्योग का कहना है कि इन आई पी निर्धारित कर दिया गया है। अनुबंध-III का मूलभूत उद्देश्य पाटनरोधी राशि को निर्धारित करना है जिससे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दूर होगी और अनुबंध-III के पाठ का अभिप्राय पूर्व परिपाठियों से घेरे बिना दिए गए अनुसार लगाया जाना चाहिए। उसमें यह कहा गया है कि नियम 3 (जिसमें जांच अवधि के दौरान एन आई पी के निर्धारण के संबंध में कहा गया है) और नियम 4 (जिसमें पिछले तीन वर्षों में कच्ची सामग्री/उपयोगिता/उत्पादन क्षमताओं के सर्वोत्तम उपयोग तथा क्षति को रद्द करने के लिए जांच अवधि के बारे में कहा

गया है) के बीच एक सौहार्दपूर्ण संरचना होनी चाहिए क्योंकि क्षति के मूल्यांकन के उद्देश्य से अवधि के चयन के संबंध में दोनों नियमों के बीच विरोधाभास है। पाटनरोधी महानिदेशालय द्वारा नियम 3 का पालन किया ही जाना चाहिए और एन आई पी का निर्धारण केवल जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

iii. पाटनरोधी शुल्क की मुद्रा अमरीकी डॉलर में रखी जानी अपेक्षित है क्योंकि रूपए का अत्यधिक मूल्यहास होता है।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्रकटन पश्चात स्तर पर उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है उनका समाधान निम्नलिखित रूप में किया गया है:

- i. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है। महानिदेशक, प्रणालियों से ही आंकड़े मंगाए गए थे जो डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से मेल खा रहे हैं। डी जी सी आई एंड एस के अनुसार आयात की मात्रा, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में सूचित की गई मात्रा, जोकि चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों से है, से काफी कम है। चीन सरकार चीन के निर्यातिकों अथवा आयातकों ने आंकड़ों के संबंध में या भारतीय आयात आंकड़ों और चीन के सीमाशुल्क आंकड़ों के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। डी जी सी आई एंड एस में बताई गई मात्राएं उपर्युक्त तुलना और विश्लेषण के लिए पर्याप्त हैं, अतः प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों पर विश्वास करने के लिए इसे उपर्युक्त माना है जैसा कि मूल जांच के दौरान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अंतिम जांच परिणाम निकला।
- ii. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए दिनांक 01 मार्च, 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011-सीमाशुल्क (एन.टी.) के अनुबंध III में सिद्धांत उल्लिखित हैं। इस मामले के लिए एन आई पी उपर्युक्त नियम का पालन करते हुए निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग का विरोध उस नियम के प्रतिकूल है और स्वीकार्य नहीं है।
- iii. मूल अंतिम जांच परिणाम में दायित्व रूपए में लगाए गए थे और प्राधिकारी ने उसी दायेका पालन करने का निर्णय लिया।

#### ४. निष्कर्ष

93. उपरोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:-

- i. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारत को उनके सामान्य मूल्य से कम पर किए गए हैं।
- ii. घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- iii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण आर्थिक क्षति हुई है।
- iv. यदि मौजूदा शुल्क लगाए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति और बढ़ेगी तथा पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के पर्याप्त कारण हैं।

#### भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

94. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं से विनिर्मित उत्पाद की कीमत स्तर पर इस उत्पाद की प्रतिस्पद्धा के संबंध में कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपाय लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पद्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय लागू करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुचित प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रुकेगी तथा उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा अधिक स्रोतों को बना कर रख सकते हैं।

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतिस्पद्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन-रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

### **त. सिफारिशें**

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू की गई थी और उसका संचालन किया गया था तथा सार्थक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति के प्रतिकरण के लिए पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए।

97. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे तालिका के कालम 9 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यकत समझते हैं।

#### **शुल्क तालिका**

क्रमांक	टैरिफ़ की मद *	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (रूपए)	मापन यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8452 30	सीविंग मशीन नीडल्स	कोई भी विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	1,54,732	लाख अदद
2.	8452 30	सीविंग मशीन नीडल्स	कोई भी विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1,54,732	लाख अदद
3.	8452 30	सीविंग मशीन नीडल्स	कोई भी विनिर्देशन	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	1,54,732	लाख अदद

\*सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और शुल्क का निर्धारण पीयूसी के वर्णन के अनुसार किया जाएगा।

98. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3 क, 3 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़ कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

99. इस अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

डा. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce )**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2017

**(Final Findings)**

Subject: Sunset Review of anti-dumping duty investigation concerning imports of Sewing Machine Needles originating in or exported from China PR.

**F. No.15/02/2016-DGAD.**— 1.M/s Altek Beissel Ltd. (hereinafter referred to as petitioner or the applicant) had filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Sewing Machine Needle (hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from China PR, was initiated by the Authority vide notification No.14/10/2010-DGAD dated 19<sup>th</sup> May, 2010 and the Authority had notified final findings on 6<sup>th</sup> May, 2011 recommending definitive antidumping duty on the imports of Sewing Machine Needles originating in or exported from China. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods by Ministry of Finance vide Customs Notification No. 50/2011-Customs, dated 22<sup>nd</sup> June, 2011.
3. Whereas, the Authority, on the basis of the application with sufficient evidence filed by the applicant, issued a Notification No.15/02/2016-DGAD dated 10<sup>th</sup> June, 2016, published in the Gazette of India, initiating a sunset review investigation in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of the duties in respect of the subject goods, originating in or exported from, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 21<sup>st</sup> June, 2017, vide Notification No.37/2016-Customs (ADD) dated 4<sup>th</sup> August 2016.
4. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.

**A. PROCEDURE**

5. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
  - i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicant on behalf of the domestic industries, alleging continuation of dumping of "Sewing Machine Needles from China PR".
  - ii. The Authority notified the Embassy of China in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

- iii. The Authority issued a public notice dated 10<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
- iv. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users and the Domestic Industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- v. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR, (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules:
  - 1. Haimen City Meitu Needle Making Co. Ltd
  - 2. Jiangsu Mais Sewing Machine Needles Co Ltd
  - 3. Haimen Dali Sewing Machine Needles Co Ltd
  - 4. Sword Machine Needle Co Ltd
  - 5. Flying Tiger Needles Co Ltd
  - 6. Nan Fang Needle Co Ltd
- vi. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit.
- vii. However, in response to the above notification, none of the exporters have filed response to the exporter's questionnaire.
- viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification along with Importer's Questionnaires to the following known importers/users/user associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4).:
  - 1. Madura Coats Private Ltd
  - 2. Aswin Intercontinental
  - 3. Groz Beckert Asia Private Ltd
  - 4. Kohinoor Impex
  - 5. Sunny International
  - 6. Paul Bros Company Pvt Ltd
  - 7. Sleek Corporation
  - 8. Needle Industries (India) Private Limited
- ix. However, no questionnaire response has been received from any importer of the subject goods. But one of the importers namely, Embroidery Card Creator has filed representation opposing imposition of duty on quilting machine needles.
- x. China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products, an association of exporters from the subject country, has also only filed submissions though without a detailed Questionnaire response. Submissions made by them have also been taken into account in the present determination.

- xii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6 (7).
- xiii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiv. Period of Investigation in the instant investigation is from January, 2015 to December, 2015. The injury investigation period covered is 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the Period of Investigation (POI).
- xv. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. Non-injurious price has been determined based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. Transaction wise data was called from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the same has been adopted in this notification for determination of volume and value of imports of the product concerned in India. The data has also been called from DG-Systems. The petitioner has relied upon the export data from China Customs for injury analysis, the same source which was used at the time of filing the petition. The Authority also relied on China Customs data at the time of initiation as given by the petitioner, however on receipt of detailed transaction by transaction data from DGCIS during the investigations; the same has been relied upon for analysis for this final finding.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the party providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
- xix. The Authority held an oral hearing on 20<sup>th</sup> February, 2017 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6). The interested parties who had presented their views in the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were provided opportunity to offer rejoinder submissions to the views expressed by opposing interested parties. The Authority has considered submissions received from the interested parties appropriately.

- xix. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.
- xx. A Disclosure Statement was issued on 30.03.2017 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 06.04.2017 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxi. \*\*\*in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$ = Rs. 64.60.

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

- 6. The product under consideration is “Sewing Machine Needles” originating in or exported from China PR.

### **B.1 Submissions by the Domestic Industries**

- 7. The submissions made by Domestic Industry are as follows:

- i. The scope of the product under consideration, under the present investigation includes sewing machine needles meant for both household and industrial purposes. These are of various sizes, and point style (normal, ball point, leather point etc.). There are many types of needles, which are used for sewing woven, knit garment, leather, embroidery etc. The different needles are known by “Systems”. Within each System, there are many sizes of needles. For each size there could be many point styles.
- ii. Sewing machine needle manufacturing is a closely held technology. Manufacture of a needle involves more than 100 steps with 12 major steps. Sewing machine needle is a very precise tool manufactured to micron accuracy. However sophisticated the sewing machine may be, a needle determines the performance of sewing productivity and aesthetic finish of the sewn product.
- iii. Machines required for manufacture of needles are Special Purpose Machines designed by needle manufacturers themselves and are not available elsewhere. The machinery used for manufacture of Household needles can also be used for manufacturing Industrial Sewing Machine needles of basic Systems. In the past years, the demand for Household needles has been decreasing and shifting to Industrial Needles because the professional tailors have now switched over to Industrial machines from Household machines. The prices of basic Systems of Industrial needles are also same as Household needles.
- iv. Sewing Machine Needle is fitted into a sewing machine and used for sewing a number of products. Needles are used for a large variety of applications, important among them being sewing of woven garments, knit garments, embroidery, and leather. Besides, there are a number of other applications such as furnishings, doll making, book sewing, vehicle seat covers etc. Sewing Machine Needle is normally produced and sold in numbers. However, the import information reflects volumes in weight (Kgs). The

industrial norm for conversion of weight to numbers is: 1 Kg = 1,667 needles. Sewing Machine Needles are normally packed in small boxes, each box containing ten needles. This is the standardized packing both in the domestic and international market.

- v. The subject goods fall under Chapter 84 and are imported under HS code subheading 8452 30 besides many other subheadings.
- vi. There is no difference in the technology employed and the quality of the domestic and imported product. The petitioner is producing and selling the product under consideration to several consumers in India and internationally (in developed and developing markets).
- vii. The petitioner has stated that they are manufacturing all kinds of sewing machine needles from the beginning of their manufacturing activity. On a specific query the petitioner stated that quilting machine needles are also manufactured by them and they were manufacturing the same even during the original investigation. The petitioner has supported his claim with product catalogue for all kinds of needles which also includes quilting machine needles.

### **B.2 Submissions by the other interested parties**

- 8. The Embroidery Card Creator has stated that ‘Quilting Machine Needle’ should not be considered as the product under consideration. The word Sewing Machine Needle should refer to those needles which are used only in sewing and which are being manufactured in India and import could cause injury to the Domestic Industry. ECC further stated that there is no domestic manufacturer of Quilting Machine Needles in India and quantum of imports of the item is very limited. Their representation is to exclude quilting machine needles from the definition of Product under Consideration from the current investigation as well as clarify the same for the previous duty notification also.

### **B.3 Examination by the Authority**

- 9. The Product under Consideration in the present investigation is “Sewing Machine Needles”. The scope of the product under consideration includes sewing machine needles meant for both household and industrial purposes in various sizes and point style (normal, ball point, leather point, etc.). Sewing Machine Needle is fitted into a sewing machine and used for sewing a number of products. Needles are used for a large variety of applications, important among them being sewing of garments, embroidery and leather. Besides, there are a number of other applications such as furnishings, doll making, book sewing, vehicle seat covers, etc.
- 10. The Authority notes that one importer namely Embroidery Card Creator, has contested the meaning and scope of the product under consideration as defined by the Authority on the grounds that the item namely quilting machine needles is neither covered under the scope of sewing machine needles nor manufactured by the Domestic Industry. However, examination of the facts of the case has revealed otherwise. The authority noted the claim of the Domestic Industry that they are manufacturing the quilting machine needles. The Authority therefore holds that there is no merit in the claim of ECC for excluding quilting needles from the scope of the subject goods.
- 11. The product under consideration remains the same as in the original investigation. The product is classified under Chapter 84 of the Customs Tariff Act under HS code 8452 30. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **B.4 LIKE ARTICLES**

12. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:-  
*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*
13. The Domestic Industry has claimed that the subject goods produced by the Domestic Industry are identical to the product under consideration being imported into India. The Domestic Industry has claimed that there is no known difference in applicant's product and product under consideration exported from the subject country and the two are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.
14. The Authority further notes from the information available on record that the product under consideration produced by the Domestic Industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the Domestic Industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority had examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigation, which mutatis mutandis is relied upon in the present review investigation. The goods produced by the Domestic Industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably and are like article within the meaning and scope of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.
15. Thus, the Authority holds that product under consideration produced by the applicant Domestic Industry is a like article to the subject product under consideration imported from subject country in accordance with the AD Rules.

#### **C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

##### **C.1 Submissions by the Domestic Industry**

16. Following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to scope and standing of the Domestic Industry:
- i. The petition has been filed by M/s Altek Beissel Ltd., Kelambakkam. There were three more producers of the product under consideration in India. M/s. TVS Sewing Needles Limited has suspended operations, allegedly as a result of continued dumping. The other two producers, M/s. Schmetz India Private Ltd. and M/s. Groz Beckert Asia Private Ltd., are not eligible because they are 100% subsidiaries of a Germany company existing in EOU which are importing various needles from their respective German parent companies for resale in India and are also exporting their entire production to their parent company in Germany.
  - ii. M/s Altek Beissel Ltd. is the only eligible domestic producer of the subject goods in India and constitutes Domestic Industry under Rule 2(b) of the Rules, 1995.

- iii. Petitioner has not imported the subject goods. Petitioner is not related, either directly or indirectly, to any exporter or importer of product under consideration in the subject country. Thus the petitioner is eligible Domestic Industry under Rules 2(b) and 5(3) of the AD Rules.

### **C.2 Submissions by other interested parties**

17. None of the producers/exporters/importers/other interested parties has made any submissions in this regard.

### **C.3 Examination by the Authority**

18. Rule 2 (b) of the AD rules defines Domestic Industry as under:

*“(b) “Domestic Industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘Domestic Industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”*

19. The application has been filed by M/s Altek Beissel Ltd., Kelambakkam. Other known producer, M/s. TVS Sewing Needles Limited has suspended operations. M/s. Schmetz India Private Ltd. and M/s. Groz Beckert Asia Private Ltd. which are 100% subsidiaries of their parent company in Germany, export their entire production to their parent company, and also import various kinds of needles from their respective German parent companies for re-sale in India. Accordingly, the authority holds that that the petitioner satisfied the requirement of standing under Rule 5(3) and constitutes Domestic Industry within the meaning of Rule 2(b).

## **D. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

### **D.1 Submissions by the Domestic Industry**

20. The views of the Domestic Industry are as follows:

- i. No response has been submitted by any exporter of the subject goods from the subject country. The only submission is made by China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products (“CCCME”). There is no exporter questionnaire response submitted either.
- ii. The Authority may kindly direct these interested parties to provide such information (in the form of exporters’ questionnaire, details of CCCME, and list of members of CCCME) or at least the non-confidential summarization of the information, so that the Domestic Industry would be able to defend its interests.
- iii. As per the anti-dumping law and rules, the exporters should file the questionnaire response and should provide a non-confidential version of the same to the other interested parties. However, in the present investigation, no such information is provided by the exporters and as a result, the Domestic Industry is not able to exercise its right to defend itself against the allegations put forward by the exporters’ association.

- iv. The Domestic Industry has not claimed any information as confidential which is available in public domain. In fact, if the information were available in public domain, nothing would have prevented these interested parties from procuring it. As a matter of fact, CCCME have claimed that they have collected the audited accounts of the petitioner from the website of Ministry of Corporate Affairs (“MCA”). CCCME can claim access to only such information which is available with MCA.
- v. Proforma IV A has been provided by the Domestic Industry with duly indexed figures and the same is as per the established practice.

#### **D.2 Submissions by the other interested parties**

21. The sole responding exporters' association, China Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products has in their submissions stated as follows.

- i. The purpose of Rule 7 is to enable all interested parties in an anti-dumping investigation to have a sufficient understanding of the information provided on confidential basis to the Authority. The non-confidential version of the petition should allow parties to exercise their rights of defence throughout the investigation.
- ii. The non-confidential version of the present petition failed to meet the standards laid down in Rule 7.
- iii. The Domestic Industry has claimed excessive confidentiality and filed an incomplete petition.
- iv. The Authority should direct the Domestic Industry to immediately provide an updated Proforma IVA to the other interested parties with the indexed figures.

#### **D.3 Examination of the Authority**

22. The Authority made available non confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

*“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is*

*either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

24. The WTO Agreement on Anti-Dumping provides as follows with regard to confidentiality of information-

*“Article-6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.*

*Article-6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.*

*Article-6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.*

*Footnote to Article 6.5.2 (footnote 18 of the WTO Agreement on Anti-Dumping) provides as follows:— Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.”*

25. It is thus evident that the public notices issued by the authorities are directly subjected to confidentiality provisions and should protect confidentiality of information provided by an interested party. Further, a conclusion drawn by the Authority based on confidential information also becomes confidential, if disclosure of such conclusion can in any way effectively lead to disclosure of information provided on confidential basis.

26. The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down at Rule 16 of the Anti-dumping Rules. Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to “respective interested parties”, while non-confidential facts are required to be disclosed to all interested parties. At no stage the Designated Authority is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests.

27. Disclosure of the commercially sensitive and confidential information, provided by the interested parties to the Designated Authority, by reposing trust and confidence, to facilitate the investigation, will completely vitiate the market atmosphere both in the domestic as well as international fronts. The disclosure of confidential information relating to the cost of production, non-injurious price etc. of the Domestic Industry will provide undue advantage to its domestic as well as overseas competitors and place them in a disadvantageous position before the consumers.

28. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims in terms of the provisions contained in anti-dumping rules and WTO Agreement. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

29. In view of the above, the Authority notes that confidential information cannot be disclosed to the interested parties with competing and conflicting interests. However the non – confidential information has been disclosed to the interested parties.

## **E. Miscellaneous Submissions**

### **E.1 Submissions by the Domestic Industry**

30. Following miscellaneous submissions have been made by Domestic Industry:

- i. Domestic Industry continued to suffer even after imposition of Anti-Dumping Duty due to multiple reasons – (a) circumvention of existing ADD by Chinese exporters, (b) evasion of existing ADD by Indian importers and (c) inadequate quantum of ADD earlier imposed leading to landed price of imports remaining below cost of production of the Domestic Industry.
- ii. Import data shows significantly high imports of subject goods from Malaysia, Singapore, UAE, Sri Lanka, Vietnam, Switzerland, and UK at extremely low prices. As per the petitioner's independent research the manufacturing facilities to that extent do not exist in these countries leading to an understanding that these are not imports of the product under consideration produced in these countries and these goods have actually been produced in China and exported through these countries.
- iii. It would also be seen that imports from other countries such as Korea, Germany, Japan, Czech Republic are at prices materially higher than Chinese prices which happen to have their own manufacturing facilities.
- iv. The petitioner adopted China customs for volume and value of imports from China as there exists significant difference between the data procured from DGCI&S and China Customs suggesting that DGCI&S has not captured the entire data.
- v. There have been past cases wherein the DGAD has not adopted information published by DGCI&S and has instead adopted information from other sources, including questionnaire responses of the exporters, customs data of the exporting country or secondary sources in India.
- vi. The gaps in China export data and DGCIS import data could be more appropriately answered by CCCME, however, CCCME has chosen to conveniently ignore to address the issue of disappearance of 9310 lacs pieces reported in China customs as exports to India.
- vii. Further, the less data would indicate that the demand for the product under consideration in India has declined to such levels but there is no information – public or otherwise – to show that there is severe decline in demand thus pointing to inaccuracy of data reported by DGCI&S.
- viii. The imposition of ADD will not stop the imports but only create a level playing field for the Domestic Industry vis a vis alleged dumped imports.
- ix. The claim of CCCME that major producers of needles in China have gone bankrupt is not correct as there is no such dramatic decline in exports of needles from China indicating closure of manufacturing units.

- x. Goods have been exported from China at an average price of 0.42 per needle as against export from other countries which is at a price in the range of Rs. 2.45-8.08 per piece. Therefore, exports from China are definitely being dumped into India.
- xi. There is no question of price undertaking between Chinese enterprises and the petitioner.

### **E.2 Views of the opposing interested parties**

31. The views of the opposing interested parties are as follows:

- i. During the Public Hearing it was argued by the Domestic Industry that imports from China PR is only 72 lac pcs against total imports of around 3469 lac pcs. This means that imports from China PR constitutes only 2% of the total imports. This decline in imports is on account of high anti-dumping duty to the tune of 2151% making imports impossible.
- ii. Even if Domestic Industry operates at 100% capacity, it will not be able to meet more than 23% of the total demand. And even after the imposition of unheard 2125% anti-dumping duty to Chinese products, the Petitioner had only operated at 53% capacity at most.
- iii. Some big exporters in China which were mentioned in the original anti-dumping investigation, including Haimen Meitu Needles Co., HaimenLida Needles Co., Sword Needles Co. and the Southern Needles Co., have gone bankrupt after imposition of ADD. Now, the Chinese sewing needle industry has only less than ten enterprises, all of which confront capacity slash. There are only three Chinese enterprises participating in this present sunset review investigation.
- iv. The three Chinese enterprises who are participating in defense of SSR investigation are actually not eligible to respond to the exporter questionnaire as they have no export record during the period of sunset review investigation, and thus have no choice but to partially give up defense for the dumping part of this investigation.
- v. Products from China are meant for the low-end market and household users in India. Thereupon, the major competitors of the Petitioner are Korea RP and Taiwan companies, and not Chinese producers.
- vi. The Chinese enterprises are seeking price undertaking with the Petitioner in order to limit the export volume and price to India. Throughout this, the demand of Indian downstream customers will be catered, and the Petitioner may not be too concerned about the import of Chinese products.

### **E.3 Examination of the Authority**

- 32. As regards the argument of the interested parties that there is a demand supply gap, the Authority notes that it is a well settled principle of law that the Domestic Industry is not obliged to fulfil the entire demand in the domestic market. Since imposition of anti-dumping duties do not prevent import and its intent is only to rectify an unfair position due to dumping, the user sector can always import and fulfil their extra demand.
- 33. As regards the argument regarding circumvention; the Authority notes that this is a sunset review investigation of anti-dumping duty and not an anti-circumvention proceeding. Therefore, the examination of this aspect is beyond the scope of this investigation.

34. As regards the argument that DGCI&S data has not captured the entire imports from China, the Authority notes that there exists a vast difference in imports as per China Customs and imports as per DGCI&S. The Difference is alarming but still it cannot be held that the goods destined for Indian market has been diverted to third countries because total import figures are also not reflective of this allegation. The Authority thereafter widened the scope of search and called import data for the PUC under various other HS codes from DGCI&S and also procured data from DG Systems. The additional import data furnished by DGCI&S compiled on transaction wise basis has now been considered for injury analysis.
35. As regards the argument that the producers in subject country wishes to undertake price undertaking with the Domestic Industry, the Authority notes that the price undertaking can only be between the Authority and the exporters and that also when the exporters from the subject country has co-operated with the Authority. None of the exporter from the subject country has co-operated with the Authority and thus question of price undertaking does not arise.

**F. Market Economy Treatment, Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin**

**F.1 Submissions by the Domestic Industry**

36. Following submissions have been made by Domestic Industry: :

- i. China is a non-market economy country. Further none of the exporters satisfy each and every condition developed from jurisprudence to qualify for grant of market economy status. Thus, the Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- ii. India is an appropriate surrogate country for China as it would result in access to accurate and adequate information. Further, India has been considered as an appropriate surrogate country by other investigation authorities too.
- iii. The normal value has been determined accordingly on the basis of cost of production in India, duly adjusted, in view of the fact that the selling price is a loss making price.
- iv. The petitioner has relied upon transaction wise import data provided by China Customs for calculation of export price.
- v. In view of significant difference in the cost of and price of various product types, petitioner have determined separate export price for each product type.
- vi. EU and USA have held India as an appropriate market economy third country in a number of cases. There is no reason to reject the observations and determinations of the EC merely because margins determined by them are higher than the margins determined by India. Even though the export price of the product from China to Europe is higher than that to India, the dumping margin in India is lower compared to dumping margin determined by Europe.
- vii. Petitioner has given detailed information on consumption of raw materials, conversion cost and other relevant pricing data to the Designated Authority as per the prescribed formats.

## **F.2 Submissions by the interested parties**

37. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to dumping margin.

## **F.3 Examination By The Authority**

38. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in China to provide the relevant information.
39. The Authority notes that the known Chinese producers/exporters and the Government of China have been adequately notified about the requirement of submission of information in the form and manner prescribed and adequate opportunity was also granted to them to make their submissions in this regard. None of the exporters/producers from China PR have co-operated with the Authority and responded to the present investigation. Further, none of the interested parties have provided any other alternative basis, as defined in the Rules, on which normal value can be determined.
40. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceeds with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

41. As per the above provisions normal value in China is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country, or the constructed value in a market economy third country, or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include reasonable profit margin.

42. Thus, in the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country the Designated Authority has constructed the normal value in China on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Authority has determined the Normal Value for the subject goods exported by all exporters in China by considering the optimum cost of Domestic Industry and after providing profit at 5% of cost of sales excluding interest.

#### **Normal value and Export price for all exporters in China**

43. As none of the producers/ exporters from China have participated / co-operated in this investigation, the Authority has determined the normal value on the basis of best facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. The net export price at ex-factory level, in respect of all exporters from China PR, is determined after making the due adjustments for Ocean Freight, Marine Insurance, FOB Price, Port Expenses and Freight Expenses. The constructed normal value, net export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject goods so determined is as mentioned in the table below.

#### **Dumping Margin**

44. Considering the constructed normal value and ex-factory export price as proposed above, the dumping margin for all exporters of the subject goods from the subject country is calculated as below:

Constructed Normal Value		Net Export Price		Dumping Margin		Dumping Margin	
Rs/Lac Pieces	US \$ / Lac Pieces	Rs/Lac Pieces	US \$ / Lac Pieces	Rs/Lac Pieces	US \$ / Lac Pieces	%	%
***	***	***	***	***	***	***	950-1000

### **G. Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link**

#### **G.1 Views of Domestic Industry**

45. Following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to injury, likelihood of injury and causal link::

- i. There is continued dumping of the product under consideration from China.
- ii. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty cease to exist.
- iii. The performance of the Domestic Industry has improved in terms of various economic parameters.
- iv. The domestic sales have steadily gone up in the least three years and have now reached break-even. At any point of time, there are at least a billion needles in stock inside the country because various dealers around the world keep importing containers full of needles. China does not have a system of sole distributor and sells directly as well as through dealers. Therefore, each one acts independently with no coherent plan. Therefore, it takes time for anti-dumping duty to make necessary impact.
- v. Demand for petitioner's needles has gone up and as a result, the petitioner has decided to make investment to modernize and upgrade production to improve productivity, safety and automate operations and this leads to huge capital investment by the

petitioner. The overall impact of this investment can be seen on the profitability in due course.

### **G.2 Views of other interested parties**

46. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. Even if the Domestic Industry operated at 100% capacity, it will only meet 15% of the total demand in India. In such situation, imports in India are imperative and bound to come. Even after imposition of 2000% duty, 94% of demand is met by imports.
- ii. Even after getting protection of 2000% in the form of anti-dumping duty, the overall profitability of the Domestic Industry deteriorated further. During the POI in the original investigation, Cash profit was (10) and has become (175) during the POI of present SSR. If existing duty level is insufficient and has not yielded positive results, then with a claim of almost 100-600% dumping margins in the present review investigation will surely not help the Domestic Industry to improve its profitability.
- iii. Cost data of Altek (the P& L accounts submitted by ALTEK with the MCA) as mentioned on the website of Ministry of Company Affairs, Government of India, does not match with the profit claimed by the Domestic Industry in its petition. does not match with the.
- iv. The petition is silent about impact of dumping on employment. Despite reduction in installed capacity, the Domestic Industry has increased the number of employees and wages. DI's employment and productivity per days has increased.
- v. Trend of Cost of Production (COP) claimed by Domestic Industry is not matching with the information contained in the Audit Reports submitted to the Ministry of Corporate Affairs and the claims made in the petition are not matching.
- vi. Injury suffered by Domestic Industry is caused by factors other than imports from China. The petitioner fails to address a number of crucial issues which had an impact on the Domestic Industry.

### **G.3 Examination by the Authority**

47. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on and has analysed injury to the Domestic Industry considering the facts available on record and applicable laws.

- i. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
- ii. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the

like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

- iii. As regards the impact of the dumped imports on the Domestic Industry, Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows.

*"The examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

- iv. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- v. For the examination of the impact of imports on the Domestic Industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

### **Demand and Market Share**

48. The Authority has defined demand or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of imports from all sources and domestic sales of the Indian producer/s. The demand so assessed, based on DGCI&S data and also on China Customs data (as given by the petitioner) is as below: -

#### **i. AS PER DGCI&S DATA**

Demand	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Subject Country	Lac Pcs	41	11	12	151
Other Countries	Lac Pcs	1,491	1,156	1,194	1,126
Sales of Domestic Industry	Lac Pcs	274	327	355	366
Total Demand	Lac Pcs	1,805	1,495	1,560	1,642
<b>Market share in Demand</b>					
Subject country	%	2%	1%	1%	9%
Other Countries	%	83%	77%	76%	69%
DI domestic Sales	%	15%	22%	23%	22%
Total		100%	100%	100%	100%

49. The demand over the injury period and POI has increased. The base year is showing a slightly high level of demand. The share of subject country has increased during the entire period as

against the share of other countries. The sale of Domestic Industry has increased as compared to base year and they have been able to hold the market during the rest of the injury period.

**ii. AS PER CHINA CUSTOMS DATA**

Demand	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Subject Country	Lac Pcs	3,288	2,553	1,853	1,849
Other Countries	Lac Pcs	3,717	3,941	3,223	3,469
Sales of DI	Lac Pcs	274	327	355	366
Total Demand	Lac Pcs	7,279	6,821	5,431	5,683
Market share in Demand					
Subject country	%	45.17%	37.43%	34.12%	32.53%
Other Countries	%	51.06%	57.77%	59.34%	61.04%
DI domestic Sales	%	4%	5%	7%	6.43%
Total		100%	100%	100%	100%

50. The petitioner has submitted that the demand for the product under consideration has declined over the injury period. The share of subject country in demand has also declined, however remains significant whereas the share of the Domestic Industry has barely increased by 2.43% over the injury period and remains at low level.

## H. Volume Effects of Dumped Imports

### Import volumes and market share in imports

51. With regard to the volume of the alleged dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCIS. The data as per China customs given by petitioner is also tabulated below.

**i. AS PER DGCI&S**

Imports Volume	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
China	Lac Pcs	41	11	12	151
Other Countries	Lac Pcs	1,491	1,156	1,194	1,126
Total Imports	Lac Pcs	1,531	1,168	1,205	1,276
Subject Imports in relation to					
Consumption	%	2%	1%	1%	9%
Production	%	10%	3%	2%	31%

52. The Authority notes that imports of the subject goods from subject country have declined during POI as compared to base year, however, the imports are still significant. Imports in relation to production and consumption have increased and are still hurting the Domestic Industry.

## **ii. AS PER CHINA CUSTOMS DATA**

Imports Volume	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
China	Lac Pcs	3,288	2,553	1,853	1,849
Other Countries	Lac Pcs	3,717	3,941	3,223	3,469
Total Imports	Lac Pcs	7,005	6,494	5,076	5,318
Subject Imports in relation to					
Consumption	%	45	37	34	33
Production	%	1417	555	387	386

53. The petitioner has submitted that imports of the subject goods from subject country have declined during POI as compared to base year, however, the imports are still significant. Imports in relation to production and consumption has also declined, however remains significant. The petitioner further submitted that in case the duty is revoked, the imports from China will re-capture the market.

### **I. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

54. With regard to the price effect, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with respect to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non Injurious Price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country on the basis of transaction wise data obtained from DGCI&S.

#### **i. Price Undercutting**

55. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation as shown in the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Landed price of imports	Rs/Lac piece	***	***	***	***
Landed price of imports	Trend	100	367	200	50
Net Sales Realisation	Rs/Lac piece	***	***	***	***
Net Sales Realisation	Trend	100	99	102	103
Price Undercutting	Rs/Lac piece	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range %	70-80	20-30	50-60	80-90

56. Authority notes that the landed price of the subject goods is significantly lower than the selling prices of the Domestic Industry, resulting in significant price undercutting.

### **ii. Price suppression/depression**

57. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject country, as detailed below:

Parameters	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Landed Price of Imports	Rs/Lac pcs	37,696	1,38,361	75,404	18,861
Trend	Indexed	100	367	200	50
Cost of sales	Rs/Lac pcs	***	***	****	***
		100	112	101	109
Selling price	Rs/Lac pcs	***	***	****	***
<i>Index</i>		100	99	102	103

58. The Authority notes that both, cost of sales as well as selling price has increased during the POI as against the base year, however, increase in selling price is less than the increase in costs of sales. It is further noted that the landed price of imports is below the selling price as well as the cost of sales of the Domestic Industry. The imports are thus depressing the domestic prices in the domestic market.

### **iii. Price Underselling**

59. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the Domestic Industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules. The analysis shows that the landed value of subject imports was much below the non-injurious price as can be seen from the table below.

NIP		Landed price		Injury Margin		Injury Margin	
Rs/ lac Piece	US\$/Lac Pieces	Rs/ lac Piece	US\$/Lac Pieces	Rs/ac Piece	US\$/Lac Pieces	%	%
***	***	***	***	***	***	900-950	900-950

60. It is noted from the above table that import price from the subject country is having underselling effect on the prices of Domestic Industry.

## **J. Economic parameters of the Domestic Industry**

### **i. Production, Capacity, Capacity Utilization & Sale Volume**

61. The Production, Capacity and Capacity Utilization details are as follows:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Capacity	Lac Pcs	900	900	900	900
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	Lac Pcs	395	419	479	479
Trend	Indexed	100	106	121	121
Capacity Utilization	%	44%	47%	53%	53%
Trend	Indexed	100	106	121	121

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Domestic Sales	Lac Pcs	274	327	355	366
Trend	Indexed	100	119	130	133

62. From the above information, the Authority notes that the capacity of production of the Domestic Industry has remained constant during the injury period. Production and sales of the Domestic Industry have increased over the injury period. However, capacity utilisation has remained at low level despite sufficient demand in the country.

### ii. Profit/Loss, Return of Investment

63. The profitability of the Domestic Industry is given in the table below:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of sales	Rs/Lac Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	101	109
Selling price	Rs/Lac Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	102	103
Profit/( Loss)	Rs/Lac Pcs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(193)	(95)	(146)
Profit/(Loss)	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(231)	(123)	(195)
Profit before interest	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(231)	(123)	(195)
Cash Profit	Rs. Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(292)	(87)	(223)
Return on Capital Employed-NFA	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Range	(0-10)	(15-25)	(0-10)	(10-20)

64. The Authority notes that both, cost of sales and selling price has increased over the injury period. However, the increase in cost of sales is much more than the increase in selling price. It is noted that the selling price has all along been lower than the cost of sales resulting in continued losses being suffered by the Domestic Industry. Consequently, profit before interest, cash profit and return on investment have also remained negative throughout the injury period. The petitioner has claimed that continued presence of dumped imports in the Indian market from the subject country is preventing the Domestic Industry from raising its prices in proportion to increase in costs.

### iii. Inventories

65. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average Inventory	Lac Pcs	17	19	28	32
Trend	Indexed	100	115	168	189

66. It is noted that inventories with the Domestic Industry have increased over the injury period.

#### **iv. Productivity**

67. From the information given below, the Authority notes that Productivity in terms of productivity per day as well as per employee has increased, which is commensurate with the level of production.

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Productivity Per Employee	Lac Pcs	3	3	4	3
Trend	Indexed	100	100	118	113
Productivity Per Day	Lac Pcs	1.08	1.15	1.31	1.31
Trend	Indexed	100	106	121	121

#### **v. Employment and Wages**

68. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
No of Employees	No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	103	108
Wages	Rs/lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	139	138
Wages Per Employee	Rs in Lacs per employee	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	135	128

69. It is noted from the table above that the Employment and wages paid have increased over the injury period.

#### **vi. Magnitude of Dumping**

70. The dumping margin determined in respect of the producers/exporters from the subject country is significant.

#### **vii. Growth**

71. The Authority notes from the table below that the Domestic Industry has registered positive growth in terms of production and sales volume. However, the performance of the Domestic Industry in terms of price parameters such as profits, cash profits and return on investment has been adverse.

Growth	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Production	%	--	6%	14%	0%
Domestic Sales Volume	%	--	19%	9%	3%
Capacity Utilization	%	--	3%	7%	0%
Profit	%	--	***	(***)	***
Cash Profit	%	--	***	(***)	***
Return on Capital Employed	%	--	(10-20)%	10-20	(0-5)

#### **viii. Ability to raise capital investment**

72. The future investment in the sector is marred by the presence of dumped imports from subject country. The negative profitability, return on investment along with abysmal market share indicates that the ability of the Domestic Industry to raise capital investments for the sector is seriously affected due to the dumped imports from the subject country.

### **ix. Factors Affecting Domestic Prices**

73. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. The dumped import prices from subject countries are directly affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market. It is also noted that the landed value of subject goods from subject countries are far below the non-injurious price of the Domestic Industry. Further, landed value from subject countries had suppressed / depressed the prices of the Domestic Industry causing financial losses to them. The imports of the product under consideration from countries other than subject countries are not injuring the Domestic Industry or are at non-dumped prices as the prices offered by these countries are significantly higher. Demand for the product is showing an increase trend and, therefore, could not have been a factor responsible for price depression and suppression faced by the Domestic Industry. It is thus evident that the dumped goods from subject countries are responsible for the depressed and suppressed prices of the Domestic Industry.

### **x. Overall assessment of Injury**

74. After examining and analysing the facts and figures concerning injury to the Domestic Industry, the Authority concludes that despite the presence of anti-dumping duties, significant imports from China are entering at dumped prices. Dumped imports are significantly undercutting the prices of the Domestic Industry. The landed price of imports is not only below selling price of the Domestic Industry but also below cost of production and non-injurious price of the Domestic Industry. Both dumping margin and injury margin in the POI are positive and significant. Dumped imports from the subject country are depressing the prices of the Domestic Industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping. Performance of the Domestic Industry has shown improvement in terms of production and sales volumes. However, the Domestic Industry the performance remained negative in respect of profit and return on investment and continues to suffer losses due to its inability to increase prices in the presence of dumped imports. Thus, the Authority concludes that the Domestic Industry has continued to suffer material injury during the period of investigation.

### **K. Other Known Factors & Causal Link**

75. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the Domestic Industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression; other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the Domestic Industry.

#### **i. Volume and prices of imports from third countries**

76. The petitioner has submitted that after imposition of antidumping duties on the subject country, significant volumes of the subject goods originating in China are allegedly being transshipped through other countries to circumvent the duties. The Authority however notes that that this being a sunset review investigation of anti-dumping duty and not an anti-circumvention proceeding, the examination of this aspect in detail is beyond the scope of this investigation. It is noted that the imports from other countries are at higher prices or are negligible in terms of volume.

#### **ii. Contraction in demand:**

77. The demand of the product under consideration has declined in the POI. However, Domestic Industry has not been able to utilize its capacity to the optimum level. Thus, contraction in demand is not a possible reason for the injury suffered by the Domestic Industry.

**iii. Changes in the pattern of consumption: -**

78. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone material change and therefore could not have been the cause for the material injury suffered by the Domestic Industry.

**iv. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: -**

79. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

**v. Developments in technology: -**

80. The Authority also notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

**vi. Export performance:**

81. The petitioner has exported the product under consideration. However, the export profitability has been segregated. Further, claimed injury to the Domestic Industry is on account of domestic operations only. Hence, claimed injury to Domestic Industry cannot be attributed to exports.

**vii. Performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry:**

82. The Authority also notes that the petitioner is a single product company. Claimed injury to the Domestic Industry is only on account of product under consideration.

**L. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury**

83. The Authority has examined the contention of the Domestic Industry to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The following analysis shows that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry in the event of revocation of antidumping duties:

**i. Level of current and past dumping margin**

84. It is noted that the level of dumping margin both in the original as well as present investigation is significant. Despite significant demand in the country, the Domestic Industry could not utilize its full capacity. Further, the import of the subject goods from the subject country still continues to be at dumped prices. Given the level of price undercutting, price underselling and price suppression and considering the capacity in China and demand in India, the volume of dumped import is likely to increase further in the event of cessation of anti-dumping duty.

**ii. Volume of Imports during post POI**

85. It is noted from the DGCI&S data that the imports from China have continued even during the post investigation period, at the same level in spite of anti-dumping duty being in force, indicating further that cessation of duties may lead to an increase in intensity of imports.

**iii. Price attractiveness of Indian market**

86. The price, at which the subject goods are being exported by China PR to India, is an indicator of the likelihood of continuation of dumping. Subject imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. It is therefore noted that with the cessation of anti-dumping duty, the Indian

prices would be too attractive for the Chinese producers. Therefore, in case of expiry of duty, it is likely that exporters from subject country would further channelize their output in the Indian market in view of the significant capacity with it.

**iv. Huge Production Capacity in China**

87. As per the information furnished by the Domestic Industry, the producers of subject goods in the subject country maintain huge capacities. Domestic Industry has provided evidence of following production capacities with various manufacturers in China. They have further stated that cessation of the present duty would result in diversion of this excess quantities to India intensifying the injury to the Domestic Industry.

SN	Company Name	Capacity (Lac Pieces)
1	Jiangsu Flying Tiger Needles Co. Ltd.	7000
2	Nantong Zhongde Making Needle Co. Ltd.	4000
3	Nantong White Crane Needles Co. Ltd.	200

**v. Export orientation of Chinese producers**

88. The petitioner has analyzed the exports from China to third countries as per China customs. It is seen that exports to the tune of 83,426 Lac Pieces, were made by China to third countries, at dumped prices, over the injury period, which is more than the total demand in India. Further, dumped exports by China are significant in relation to production, sales and consumption in India. It clearly indicates that the Chinese producers are intensely focused on exports. In the event of cessation of duty, these exporters are likely to divert their exports to India at dumped prices.

**vi. Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and the Indian market**

89. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from the subject country in the market would cause an adverse impact on the Domestic Industry. This is further established by the long term dumping practice by the subject country. Given the facts of the instant case, and considering the above discussed current dumping and likelihood of dumping and injury parameters, it is submitted that dumping and consequent injury to the Domestic Industry is likely to recur in the event of cessation of anti dumping duty.

**M. Magnitude of Injury and injury margin**

90. The non-injurious price of the subject goods produced by the Domestic Industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Non Injurious Price		Landed price		Injury Margin		Injury Margin	
Rs/ lac Piece	US\$/Lac Pieces	Rs/ lac Piece	US\$/Lac Pieces	Rs/ac Piece	US\$/Lac Pieces	%	%
***	***	***	***	***	***	900-950	900-950

## **N. Post Disclosure Comments**

91. The post disclosure submissions have been received only from Domestic Industry. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

- i. With respect to volume and value of imports, DI has submitted that the volume of imports considered by the Authority is far below than the volume of imports reported in China customs data, thus requested the Authority to directly verify the China customs data.
- ii. DI submits that the NIP has been determined. The basic objective of Annexure III is to determine the amount of anti-dumping that would remove injury to Domestic Industry & the text of Annexure III should be interpreted as given without being clouded by the prior practices. It states that there has to be a harmonious construction between Rule 3 (which talks about determination of NIP during POI) & Rule 4 (which talks about best utilization of raw materials/utility/production capacities over last 3 years and POI to nullify the injury) since there is a conflict between both the rules with respect to selection of period for purpose of assessment of injury. Rule 3 must be followed by DGAD and NIP should be determined by considering the data relating to cost of production for POI only.
- iii. The currency of ADD is required to be kept as US\$ since the value of Rupee is depreciated significantly.

### **N.1 Examination by the Authority**

92. The issues raised at post disclosure stage have been examined and are addressed as below:

- i. The Authority has relied upon DGCI&S import data. The data was also called from DG Systems, which is matching with the DGCI&S data. The volume of imports as per DGCI&S is much less than the quantity reported by petitioner in their petition which is from China Customs data. The Government of China, exporters from China or the importers have not given any response with respect to the data or the difference between the Indian import data & China Customs data. The quantities reported in DGCI&S are sufficient for reasonable comparison and analysis, therefore, the Authority considered it appropriate to rely upon DGCI&S import data as was done during the original investigation resulting in the final finding.
- ii. Annexure III of Custom Notification No. 15/2011-customs (N.T) dated 1st March 2011 laid down the principles for determination of Non-injurious Price. The NIP for the instant case has been determined following the said Rule. The contention of the DI is contrary to the *ibid* Rule and not acceptable.
- iii. The duties in the original Final Finding were imposed in Rupee term and the Authority decided to follow the same suit.

## **O. CONCLUSION**

93. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- i. The subject goods have been exported to India from the subject country below its associated normal value;
- ii. The Domestic Industry has suffered material injury;
- iii. The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country.

- iv. In case of revocation of existing duties, the injury to the Domestic Industry will intensify and there is sufficient cause for the continuation of anti-dumping duties.

### **Indian Industry's Interest And Other Issues**

94. The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.
95. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

### **P. RECOMMENDATIONS**

96. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the Domestic Industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.
97. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col No.9 of the table below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

**Duty Table**

S.I. No	Tariff Item *	Description of Goods	Specifica tion	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (in Rs)	UOM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8452 30	Sewing Machine Needles	Any specificat ion	China PR	China PR	Any	Any	1,54,732	Lac pieces
2	8452 30	Sewing Machine Needles	Any specificat ion	China PR	Any	Any	Any	1,54,732	Lac pieces
3	8452 30	Sewing Machine Needles	Any specificat ion	Any	China PR	Any	Any	1,54,732	Lac pieces

\*Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.

- 
98. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
  99. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. &Designated Authority